सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 127, नई दिल्ली । गुरुवार, 18 जुलाई 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

जिंदगी से सीख लेनी है तो पीछे मुड़कर देखो, जिंदगी को जीना है तो आगे चलकर देखो!

03 मुहर्रम: दिल्ली में शियाओ ने निकाले ताजिये मनाया शोक
06 प्रदूषण से मुक्ति और सुप्रीम कोर्ट
08 41 साल बाद भारतीय पीएम का ऑस्ट्रिया दौरा कितना अहम

दिल्ली परिवहन विभाग की कार्यशैली जनहित में या कंपनियों और राजस्व में इज़ाफा करवाने के प्रति

संजय बाटला

नई दिल्ली । किसी भी राज्य में सरकारी विभाग मुख्य रूप से परिवहन विभाग जनहित और जनता को सुगम, सुरक्षित, विश्वसनीय, आरामदायक और समयानुसार जरूरी सवारी सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया जाता है और उसके बाद किसी को निम्न स्तर के कर्मचारी/अधिकारी परेशान ना करे इस लिए उच्चाधिकारी को आसिन किया जाता है।

दिल्ली भारत देश की राजधानी में परिवहन विभाग शायद जनहित में नही बल्कि बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने और राजस्व में इज़ाफा करवाने के लिए खोला गया है और उच्चाधिकारी भी उसी के प्रति समर्पित है। यह हम नहीं कह रहे यह सिद्ध हो रहा है पिछले कुछ सालों में जारी आदेशों/ दिशा निर्देशों से।

1. महिला सुरक्षा के लिए वाहनों में लगने वाले जीपीएस / वीएलटीडी डिवाइस और पैनिक बटन जिसका कंट्रोल रूम/ डाटा कलेक्शन सेंटर बनाने के नाम पर भारत सरकार से करोड़ो रुपए प्राप्त करने के बाद भी आज तक शुरु ना करके और बिना कंट्रोल रूम के ही वाहन मालिकों से उसकी नेविगेशन सिस्टम के नाम पर सालाना फीस की उग्राही के लिए डिम्ट्स नाम की कम्पनी को नियुक्त कर फीस लेना,

2. डीटीसी और क्लस्टर बसों में बिना सीसीटीवी कैमरे का प्रयोग हुए कम्पनी को फायदा पहुंचाना,

3. जनता को सार्वजानिक बस सेवा प्राप्त करने के बस क्यू शेल्टर का निर्माण करवाए/ किए बिना डीटीआईडीसी नाम की कम्पनी द्वारा स्टेज परमिट बस वाहन मालिकों से जबरदस्ती मासिक फीस वसुलवाने का दबाव बनाना,

4. ऑटो तीन पहिया सवारी वाहन सेवा के किराए में जीपीएस के लिए जनता से पर किलोमीटर/प्रति सफर का पैसा दिलवाना, वह भी जीपीएस ना लगा होने पर। स्वयं विभाग ने ऑटो तीन पहिया सवारी वाहन सेवा को 2020 में जीपीएस डिवाइस से छूट दे दी थी और आज तक छूट लागू है।

5. महिला फ्री को सभी स्टेज कैरिज परमिट वाहनों पर शुरु ना करके सिर्फ जिन को विभाग द्वारा किलोमीटर की दर से फिक्स पेमेंट करने का एग्रीमेंट है और डीटीसी जिसका पूर्ण घाटा विभाग और सरकार द्वारा देना निश्चित है में पिंक नाम का पास लेना अनिवार्य कर उसके नाम पर करोड़ों का खर्चा दिखाना (वह खर्चा जो एक हाथ से देकर दूसरे हाथ से वापिस उसी जेब में आ रहा है)

6. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा ज़ारी गैजट नोटीफिकेशन के लागू होने के बाद भी लाईसेंस/ आरसी/कंडक्टर लाइसेंस कार्ड के नाम से फीस वसूलना जैसे अनगिनत सबूत है जो यह सुनिश्चित करते हैं की दिल्ली परिवहन विभाग में तैनात किए जाने वाले आला अधिकारी जनहित के प्रति नही बल्कि बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचवाने और राजस्व में इज़ाफा करवाने के लिए कार्यरत है और इसका एक और सबूत यह भी है की अधिकतर तकनीकी पदो पर इन आला अधिकारियों ने तकनीकी अधिकारियों की जगह सांख्यिकी अधिकारी/अनुभाग अधिकारी को नियुक्त कर दिया है और इसके प्रति ना तो मुख्य सचिव और ना ही उपराज्यपाल दिल्ली द्वारा कोई टिप्पणी की गई।

जनहित के प्रति समर्पित सरकारी विभाग अगर किसी अन्य हित मे कार्य कर रहा हो तो उसे बंद कर देना ही उचित होगा या फिर दिल्ली के मुख्य सचिव और उपराज्यपाल तत्काल प्रभाव से इस के लिए किसी स्वतंत्र एजेंसी को जांच के आदेश जारी करे।

अभी भी क्यों बंद है सिंधु बॉर्डर, बड़ा सवाल ?

संजय बाटला

नई दिल्ली । फरवरी में किसानों के दिल्ली आने की संभावना को देखते हुए सिंधु बॉर्डर को सील कर दिया गया था। करीब 2 महीने बाद पुलिस प्रशासन की तरफ से लोगों को राहत देते हुए सिंधु बॉर्डर, एनएच- 44 की दो लेन को खोल दिया गया था लेकिन सड़क पर रखे हुए मलबे के ढेर को नहीं हटवाया गया था जिस कारण हरियाणा से दिल्ली आने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अभी तक फ्लाईओवर के ऊपर दो लाइन बंद हैं। इसके कारण पीक आवर्स में यहां भयंकर जाम का सामना लोगों को करना पड़ता है। इस नैशनल हाइवे से रोजाना दिल्ली में लाखों गाड़ियां एंट्री करती हैं। ऐसे में कई बार यहां कई किलोमीटर तक लोगों को जाम का सामना करना पड़ता है। वहीं रात के अंधेरे में सड़क के किनारे पड़े बड़े-बड़े सीमेंट के ब्लॉक, पत्थर के टुकड़े और मलबे के कारण कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। यह हालत सिंधु बॉर्डर फ्लाईओवर पर दोनों तरफ बनी हुई है। इस बॉर्डर पर सुबह और शाम जाम की स्थिति काफी खराब है। गाड़ियां रेंगती रहती हैं, कई बार तो एंबुलेंस भी यहां फंसी हुई नज़र आ जाती है। हरियाणा के कुंडली से दिल्ली आने के लिए जाम के कारण कई बार आधा घंटा या उससे भी अधिक समय सिर्फ बॉर्डर क्रॉस करने में लोगो को लग जाता है। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा भी सभी बॉर्डर को खोलने के आदेश पारित हो चुके हैं तो दिल्ली में सिंधु बॉर्डर पर सभी लेन खोलने में देरी क्यों ?

दिल्ली मेट्रो में शराब की बोतल लेने वाले यात्रियों को जरूरी खबर, डीएमआरसी ने जारी की नई एडवाइजरी

दिल्ली मेट्रो दिल्ली मेट्रो में शराब की बोतल ले जाने को लेकर नई एडवाइजरी जारी की गई है। डीएमआरसी ने कहा कि दिल्ली मेट्रो में उसी राज्यों की आबकारी नीति के नियम लागू रहेंगे जिस शहर में आप सफर कर रहे हैं। अगर आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली अगर यूपी में हैं तो यूपी और हरियाणा में हैं तो हरियाणा के नियम लागू रहेंगे।

नई दिल्ली । दिल्ली मेट्रो की ट्रेनों में यात्रियों को दो सीलबंद शराब की बोतलें ले जाने की अनुमति दिए जाने के मामले में संबंधित राज्यों के आबकारी नियम लागू होंगे। डीएमआरसी ने इसकी जानकारी दी है। दिल्ली मेट्रो राष्ट्रीय राजधानी के अलावा हरियाणा और उत्तर प्रदेश के शहरों में भी चलती है। इसलिए इन राज्यों में आबकारी नियम अलग हैं।

डीएमआरसी ने कहा कि यात्री अगर मेट्रो में सफर करके दिल्ली से बाहर जा रहे हैं, तो उन्हें आबकारी नियम के प्रति सावधान रहने की जरूरत है।

पिछले साल दी थी दो बोतल की अनुमति

DMRC ने पिछले साल जून में अनुमति दी थी कि एक व्यक्ति मेट्रो ट्रेनों में दो सीलबंद शराब की बोतलें ले जा सकता है। इस पर दिल्ली सरकार ने आपत्ति जताई और बताया कि यह आबकारी नियमों के खिलाफ है।

दिल्ली मेट्रो हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और नोएडा में चलती है। डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक विकास कुमार ने बताया कि दिल्ली सरकार ने जो आबकारी नीति के तहत नियम बनाया है, वह मेट्रो में लागू होंगे।

एक बोतल ले जाने की अनुमति

आबकारी अधिनियम के अनुसार, रम, वोदका और व्हिस्की जैसी शराब की केवल एक सीलबंद बोतल एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाई जा सकती है। दिल्ली मेट्रो अन्य राज्यों के शहरों में भी जाती है और यात्री को दो सीलबंद बोतले ले जाने की अनुमति देना आबकारी अधिनियम का उल्लंघन होगा।

डीएमआरसी ने क्या कहा

दिल्ली, यूपी और हरियाणा में अगर मेट्रो से सफर कर रहे हैं, तो इन शहरों में इनके राज्यों के ही आबकारी नियम लागू होंगे।

डीएमआरसी ने कहा कि अगर कोई यात्री दिल्ली में दो शराब की बोतलों के साथ ट्रेन में चढ़ता है और यूपी की ओर जाता है तो उसे समझना चाहिए कि उसके पास उस राज्य के आबकारी नियम का पालन करने के लिए दो बोतलें हैं। इसलिए, अगर केवल एक शराब की बोतल की अनुमति है, तो उसे केवल एक ही ले जाना चाहिए।

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे समेत कई मार्गों पर बंद होगा आवागमन

26 जुलाई की रात से लागू किया जाएगा डायवर्जन प्लान

कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस ने डायवर्जन प्लान तैयार कर लिया है। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे समेत कई मार्गों पर 26 जुलाई की आधी रात से वाहनों का आवागमन बंद हो जाएगा। अगर आप दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे समेत इन मार्गों से चलते हैं तो पुलिस का डायवर्जन प्लान जरूर देख लीजिए। पुलिस द्वारा इन सभी मार्गों को बंद कर दिया जाएगा।

गाजियाबाद । कांवड़ यात्रा 2024 यदि आप दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे या मेरठ रोड पर कार या हल्के वाहनों में सफर करते हैं तो 26 जुलाई की आधी रात के बाद डायवर्जन प्लान देखकर ही घर से निकलें, जिससे कि आवागमन में परेशानी का सामना न करना पड़े।

गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट ने भारी वाहनों के बाद अब हल्के वाहनों के लिए भी डायवर्जन प्लान तैयार कर लिया है, जिसे 26 जुलाई की रात 12 बजे लागू कर दिया जाएगा। यह डायवर्जन प्लान पांच अगस्त की रात आठ बजे तक लागू रहेगा।

बताया गया कि आवश्यक वस्तुओं का परिवहन करने वाले वाहनों को आवेदन के बाद अलग से सशर्त अनुमति दी जाएगी। कांवड़ियों की संख्या एवं पुलिस कमिश्नरेट की यातायात आवश्यकता के मद्देनजर डायवर्जन प्लान में बदलाव किया जा सकता है।

ये है डायवर्जन प्लान

. गंगनहर कांवड़ पटरी मार्ग, पाइपलाइन मार्ग पर सभी वाहनों का आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होगा।

. मोहननगर, मेरठ तिराहा, राजनगर एक्सटेंशन, हापुड़ चुंगी की ओर से मेरठ रोड पर मेरठ की ओर जाने वाली लेन में 28 जुलाई की रात 12 बजे से वाहनों का आवागमन पूरी तरह से बंद रहेगा।

. पलवल, कुंडली से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे से आने वाले वाहन 28 जुलाई की रात 12 बजे से दुहाई कट पर न उतरकर डासना कट पर उतरकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- नौ का प्रयोग करते हुए अपने गंतव्य को जाएंगे।

. मेरठ तिराहा से मोहननगर, सीमापुरी बॉर्डर की ओर जाने वाले वाहन 28 जुलाई की रात 12 बजे तक सीमापुरी बॉर्डर से आने वाली लेन में आवागमन कर सकेंगे, इसके बाद इस मार्ग पर वाहनों का आवागमन पूरी तरह से बंद रहेगा।

. चौधरी मोड़, नया बस अड्डा, गोशाला फाटक, हापुड़ तिराहा, कैला भट्ठा की ओर से दूधेश्वरनाथ मंदिर की ओर सभी वाहनों आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। पटेल नगर फ्लाईओवर पर भी वाहनों का आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।

. संजय गीता चौक, घूकना मोड़, डीपीएस कट, सिहानी चुंगी, संजयनगर आरओबी से मेरठ रोड की ओर वाहनों का आवागमन पूरी तरह से बंद रहेगा।

. मेरठ तिराहा से संतोष मेडिकल, जल निगम टी प्वाइंट तक वाहनों का आवागमन पूरी तरह से बंद रहेगा।

. दिल्ली- मेरठ एक्सप्रेस-वे का प्रयोग कर दिल्ली, मेरठ की ओर जाने वाले वाहन एनएच-9 का प्रयोग करते हुए हापुड़ होते हुए दिल्ली, मेरठ की ओर आवागमन करेंगे। 28 जुलाई की रात 12 बजे से डीएमई पर वाहनों का आवागमन पूरी तरह से बंद रहेगा।

. रेलवे स्टेशन रोड, किराना मंडी, रमते राम रोड, घंटाघर, बजरिया रोड, दिल्ली गेट की तरफ से आने वाले हल्के वाहन दूधेश्वरनाथ मंदिर की ओर नहीं जा सकेंगे।

. मेरठ तिराहा से हरनंदी नदी, कनावनी एवं इंदिरापुरम की तरफ किसी वाहन को नहीं जाने दिया जाएगा। वाहन चालक पुराना बस अड्डा से चौधरी मोड़, विजयनगर आरओबी के रास्ते एनएच-नौ की ओर जाएंगे।

. जीटी रोड , मेरठ रोड और मोहन नगर से वसुंधरा फ्लाइओवर के बीच सभी प्रकार के आटो को लेकर जाने पर रोक रहेगी।

हल्के वाहनों के लिए 26 जुलाई की आधी रात से डायवर्जन प्लान लागू किया जाएगा। किसी भी असुविधा से बचने के लिए डायवर्जन प्लान देखकर ही वाहन चालक घरों से निकलें। किसी प्रकार की जानकारी के लिए ट्रैफिक नियंत्रण कक्ष के हेल्पलाइन नंबर 0120 - 2986100 अथवा मोबाइल नंबर 9643322904 पर संपर्क कर सकते हैं।

- पीयूष सिंह, एडीसीपी ट्रैफिक, गाजियाबाद

संस्कारशाला: किताबें पढ़ना जीवन का हिस्सा क्यों बनाना चाहिए ?

अंकुर शरण

आज की डिजिटल दुनिया में, हम अक्सर लैपटॉप और मोबाइल फोन पर समय बिताते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि किताबें पढ़ना कितना लाभकारी हो सकता है? यहाँ हम 12 कारण बता रहे हैं कि क्यों किताबें पढ़ना आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनना चाहिए।

1. ज्ञान का भंडार:

किताबें हर विषय पर विशाल ज्ञान का भंडार होती हैं। चाहे इतिहास हो, विज्ञान, दर्शनशास्त्र या नए शौक और रुचियाँ, किताबें आपको गहराई से जानकारी प्रदान करती हैं।

2. शब्दावली में वृद्धि:

नियमित पढ़ाई आपको विभिन्न शब्दावली से परिचित कराती है, जिससे आपकी संप्रेषण क्षमता और समझ में सुधार होता है।

3. याददाश्त में वृद्धि:

अध्ययन बताते हैं कि पढ़ाई आपकी स्मरण शक्ति और संज्ञानात्मक कार्यों को तेज कर सकती है, जिससे आपका मस्तिष्क सक्रिय और जागरूक रहता है।

4. तनाव में कमी:

एक अच्छी किताब के साथ आराम करना मानसिक राहत का एक रूप हो सकता है, जिससे दैनिक चिंताओं से मुक्ति मिलती है और आपको विश्राम का अवसर मिलता है।

5. ध्यान और एकाग्रता में सुधार:

आज की तेज़-तर्रार दुनिया में, पढ़ाई आपके ध्यान और एकाग्रता को लंबे समय तक बनाए रखने की क्षमता को मजबूत करती है।

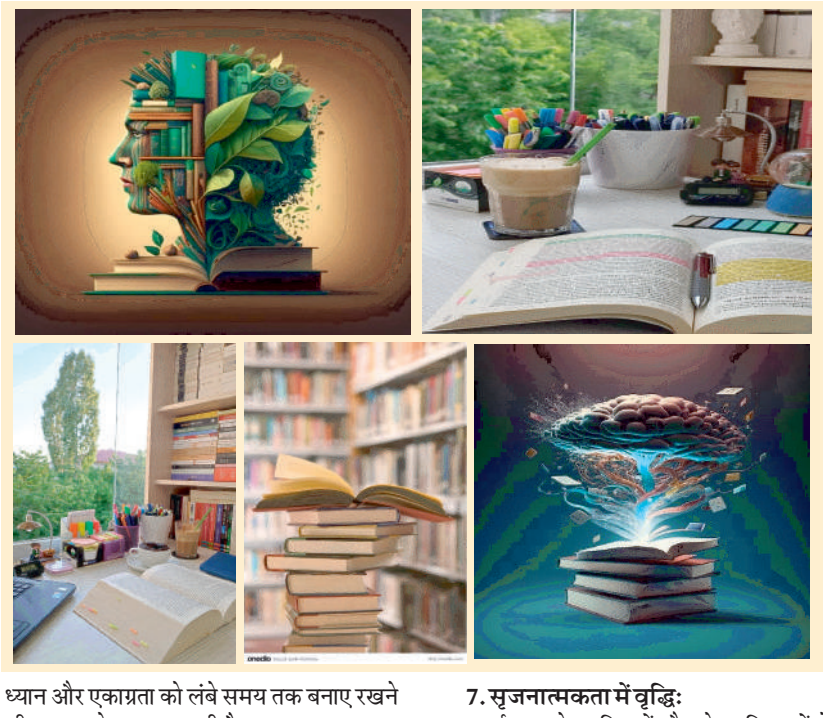

6. सहानुभूति और दृष्टिकोण:

कहानियों के पात्रों के जीवन में कदम रखने से आप सहानुभूति विकसित करते हैं और विभिन्न दृष्टिकोणों को गहराई से समझते हैं।

7. सृजनात्मकता में वृद्धि:

पढ़ाई आपको नए विचारों और सोच प्रक्रियाओं से परिचित कराती है, जिससे आपकी अपनी सृजनात्मकता और समस्या-समाधान कौशल को प्रोत्साहन मिलता है।

8. लेखन कौशल में सुधार:

अच्छी तरह से लिखी गई किताबों में डूबने से आपका लेखन शैली, वाक्य संरचना और समग्र संप्रेषण स्पष्टता में सुधार होता है।

9. नींद की गुणवत्ता में सुधार:

बिस्तर पर जाने से पहले स्क्रीन टाइम के बजाय किताब पढ़ें। पढ़ाई की शांति आपको आराम और विश्राम दिलाने में मदद करती है, जिससे नींद की गुणवत्ता बेहतर होती है।

10. नए संसारों का द्वार:

किताबें आपको विभिन्न समयों, स्थानों और वास्तविकताओं में ले जाती हैं। एक आरामदायक कुर्सी पर बैठकर रोमांचक यात्राओं, ऐतिहासिक घटनाओं या अद्भुत रोमांचों का अनुभव करें।

11. आजीवन सीखने की यात्रा:

पढ़ाई निरंतर सीखने और आत्म-अन्वेषण की यात्रा है। चाहे आपकी उम्र या रुचियाँ कुछ भी हों, हमेशा कुछ नया सीखने के लिए होता है।

12. बातचीत की शुरुआत:

किताबें बातचीत के लिए एक खजाना होती हैं, जिससे अन्य लोगों के साथ संबंध बनाने और समृद्ध चर्चाओं को प्रोत्साहित करने में मदद मिलती है।

किताबें न केवल ज्ञान का स्रोत हैं, बल्कि यह आपके मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए भी आवश्यक हैं। इसलिए, अगली बार जब आप लैपटॉप या मोबाइल फोन का उपयोग करने का सोचें, तो एक किताब उठाएँ और उसमें डूब जाएँ। यह आपकी जीवन शैली में एक सकारात्मक बदलाव ला सकती है।

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)
TOLWA
website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com
रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल - 0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण
रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

नए कल्याणकारी राज्य का आगाज

डा. अश्विनी महाजन,

हर घर में शौचालय बनने से खुले में शौच जैसे अभिशाप से मुक्ति हुई है, जिसके चित्र दिखाकर भारत को पिछड़ा दिखाने का प्रयास विदेशी अक्सर किया करते थे। महिलाएं आज सम्मान से जी रही हैं'

तीन दिसंबर 2023 को हुई मतगणना में जब चार बड़े राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में से तीन में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में काबिज होती दिखाई दे रही है, और कांग्रेस को मात्र एक ही राज्य तेलंगाना में जीत हासिल हुई है, राजनीतिक विश्लेषक भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस जीत के कारणों का विश्लेषण कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में अक्सर कांग्रेस पार्टी की सांप्रदायिक वोट बैंक, भ्रष्टाचार, वंशवाद आदि की राजनीति के मुद्दे उठाती रही है। राम मंदिर का निर्माण, धारा 370 की समाप्ति, सांप्रदायिक हिंसा (विशेष तौर पर सर तन से जुदा) जैसे मुद्दे काफी मात्रा में चर्चा में रहे। लेकिन इतिहास गवाह है कि चाहे ये मुद्दे भी महत्वपूर्ण रहे हैं, लेकिन यदि कोई पार्टी या सरकार लोगों की भलाई के लिए काम नहीं करती, तो जनता उसे कभी स्वीकार नहीं करती। वोट अनुपात के रूप में भाजपा को मध्य प्रदेश में 48.81 प्रतिशत, राजस्थान में 41.85 प्रतिशत और छत्तीसगढ़ में 46.35 प्रतिशत वोट मिलना इस बात को दर्शाता है कि पार्टी की केंद्र सरकार की योजनाओं और उनकी उपलब्धियों से जनता संतुष्ट है और इसलिए उसकी सरकार चाहती है। जाहिर है वंशवाद, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिक हिंसा के बारे में भी जनता संवेदनशील है और देश में स्वस्थ एवं विकासवादी राजनीति की स्थापना चाहती है। वो वोट बैंक की राजनीति के चलते आर्थिक-सामाजिक वातावरण को दूषित भी नहीं होने देना चाहती।

विकसित भारत बनाने का सपना : भारत का आम जन इस दंश के साथ जी रहा था कि भारत एक गरीब देश है जो अमीर देशों की अकूत संपत्ति, विकसित इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊंची आमदनी और उच्च जीवन स्तर का मुकाबला कर ही नहीं सकता। उनके बराबर पहुंचने में हमें कई सदियां भी लग सकती हैं। 2014 में भारत की अर्थव्यवस्था भी सबसे जर्जर पांच अर्थव्यवस्थाओं में शामिल थी। यहां घटते निवेश और लगातार घटती संवृद्धि दर की त्रासदी भी झेल रहा था। लेकिन मात्र 10 वर्षों से भी कम समय में भारत विश्व की दसवीं अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ता हुआ पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था तक पहुंच गया है और अगले तीन सालों से भी कम समय में चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज भारत विश्व की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भी बन चुका है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के पहले 100 वर्ष पूर्ण होने से पहले एक विकसित राष्ट्र बनने का संकल्प देकर देश के आमजन की आकांक्षाओं को नए पंख देने का काम किया है। स्वाभाविक ही है कि इन आकांक्षाओं के मद्देनजर देश की जनता ने भाजपा के नेतृत्व पर अपना भरोसा जताया है, जिसका एक नमूना मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में दिखा।

मुफ्त की योजनाओं को जनता ने नकारा : पिछले कुछ समय से कुछ राज्यों में सरकारों और राजनीतिक दलों द्वारा बड़ी मात्रा में मुफ्त की योजनाओं के दम पर सत्ता पर काबिज होने का प्रयास शुरू हुआ है। उसके कारण उन्हें कुछ हद तक सफलता भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी और उसकी सरकारों द्वारा मुफ्त की योजनाओं की झड़ी लगी हुई है। उधर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी इसी प्रकार की मुफ्त की योजनाएं बड़ी मात्रा में चल रही हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन योजनाओं को चलाने हेतु इन प्रांत सरकारों के पास पर्याप्त धन की भारी कमी है जिसके कारण वे एक ओर तो भारी कर्ज में डूबते जा रहे हैं, तो दूसरी ओर इन मुफ्त की योजनाओं के कारण वे आवश्यक मदों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आमजन को सशक्त बनाने वाली अन्य योजनाओं पर खर्च भी नहीं कर पा रहे हैं। इन चुनावों में भी दलों ने इन मुफ्त की योजनाओं की काफी घोषणाएं की। कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में किसानों के कर्ज माफ करने के अलावा मुफ्त बिजली, गैस सिलेंडर की सब्सिडी, महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह, युवाओं को 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ते के अलावा कई अन्य मुफ्त की स्कीमों की घोषणा की। इसी तरह से राजस्थान में पहले से ही कांग्रेस सरकार महिलाओं को स्मार्टफोन, सस्ता सिलेंडर, 25 लाख रुपए तक के इलाज के लिए फ्री मेडिकल बीमा, एक करोड़ परिवारों को फ्री फूड पैकेट आदि की योजनाएं तो चला ही रही थी, इस चुनाव में कांग्रेस ने पहले की मुफ्त की योजनाओं के साथ-साथ फ्री लैपटॉप, फ्री बिजली आदि की भी घोषणा की थी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन मुफ्त की योजनाओं को गलत मानते हैं और इसे रेवड़ी बांटने की संज्ञा देते हैं। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकारों ने काफी बड़ी मात्रा में कई मुफ्त की योजनाओं को चलाया है, जिसमें उज्जवला लाभार्थियों और आमजन को सस्ता सिलेंडर देना, राजस्थान में 12वीं कक्षा पास करने के बाद लड़कियों को फ्री स्कूटी देना आदि की घोषणा भी शामिल है। लेकिन यह भी सच है कि फ्री बिजली, फ्री पानी और फ्री यात्रा आदि की योजनाओं से भाजपा ने हमेशा परहेज रखा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि रेवडिया बांटने और नई रेवडियों की घोषणा के बावजूद मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीत नहीं पाई और भारतीय जनता पार्टी को जनता का समर्थन प्राप्त हुआ।

कल्याणकारी राज्य की परिभाषा बदली : अभी तक रोजगार योजनाओं के माध्यम से पैसे बांटने, मुफ्त या सस्ती बिजली-पानी, पेट्रोल, डीजल और गैस पर सब्सिडी, सस्ता राशन, शिक्षा और स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च आदि को ही कल्याणकारी राज्य की इतिश्री मान लिया जाता था। लेकिन पिछले 9 सालों से अधिक के दौरान कल्याणकारी राज्य की परिभाषा बदली है और उसमें सुधार होता दिखाई दे रहा है, जिसे जनता का समर्थन भी प्राप्त हुआ है। सबसे पहले आवास योजना में आमूल-चूल परिवर्तन के माध्यम से प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए, आवास योजना पर खर्च की वास्तविकता को सुनिश्चित करने का प्रयास हुआ है। मात्र कुछ ही सालों में लगभग 3 करोड़ घरों का निर्माण हुआ जिसमें 5 लाख करोड़ रुपए केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए और 15 लाख करोड़ रुपए स्वयं लाभार्थियों ने खर्च कर, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में अपने लिए बेहतर घरों का निर्माण किया, और बेहतर जीवन का आनंद लेना शुरू किया। एक करोड़ अतिरिक्त घरों का निर्माण भी विभिन्न चरणों में है। उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिया गया और बाद में उन गरीब महिलाओं द्वारा अपने खर्चे पर उन सिलेंडरों को रिफिल कर अपनी सुविधा को बढ़ाया गया। आज एक वर्ष में उज्जवला लाभार्थी तीन से अधिक सिलेंडर औसतन भरवाती हैं। इससे उनके स्वास्थ्य की रक्षा भी हुई है और समय की बचत भी। देश में लगभग सभी गांवों तक बिजली पहुंचाने से जीवन स्तर में सुधार तो हुआ ही है, संचार और इंटरनेट क्रांति को देशभर में ले जाने में भी सफलता मिल रही है। सभी घरों में नल से जल का लक्ष्य भी पूर्ण होने को तैयार है जिससे महिलाओं को दूर से जल लाने नहीं जाना पड़ता और उनके समय की बचत हो रही है। हर घर में शौचालय बनने से खुले में शौच जैसे अभिशाप से मुक्ति हुई है, जिसके चित्र दिखाकर भारत को पिछड़ा दिखाने का प्रयास विदेशी अक्सर किया करते थे। महिलाएं आज सम्मान से जी रही हैं। प्राथमिक चिकित्सा में सुधार और सबसे महत्वपूर्ण आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, कम साधन संपन्न लोगों के लिए एक वरदान सिद्ध हो रहा है। देखा जाए तो ये सभी योजनाएं लक्षित लाभार्थियों के लिए हैं। अभी तक ये लाभार्थी इन सुविधाओं से वंचित थे और पूर्व में राजनीतिक दल उनकी गरीबी, अभाव और बेरोजगारी को दूर करने के छलावों के साथ, उनके वोट बटोर लिया करते थे। लेकिन अब इन लाभार्थियों ने पिछले 9-10 सालों में सरकार की मदद और स्वयं के प्रयासों से इन अभावों से कुछ हद तक मुक्ति पाई है। इस तरह कल्याणकारी राज्य की परिभाषा बदल गई है।

इन कारणों से बच्चों में होती है Calcium की कमी, Parents जानें बचाव के तरीके

बढ़ते बच्चों और टीनएजर की अच्छी सेहत के लिए जरुरी है कि उनके शरीर में कैल्शियम की कमी न हो। पर्याप्त कैल्शियम उनकी हड्डियों को जीवनभर टूटने से बचाता है और उन्हें जीवन में आगे चलकर ऑस्टियोपोरोसिस जैसी गंभीर समस्या नहीं होती। यदि आप भी चाहते हैं कि बच्चों को जीवन भर हड्डियों से जुड़ी कोई बीमारियां न हो तो आप उनके डाइट में कैल्शियम और विटामिन-डी वाले आहार को शामिल करें। तो चलिए आपको बताते हैं कि बच्चों को कितनी मात्रा में कैल्शियम की जरुरत होती है....

कितनी कैल्शियम की मात्रा जरुरी ?

एक्सपर्ट्स की मानें तो बच्चों की बेहतर ग्रोथ के लिए जरुरी है कि 1 से 3 साल के बच्चों की रोजाना करीब 700 मिलीग्राम कैल्शियम की आपूर्ति हो। जबकि 4-8 साल के बच्चों को 1000 मिलीग्राम कैल्शियम की जरुरत होती है। वहीं 9 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को 1300 मिलीग्राम से ज्यादा कैल्शियम की जरुरत होती है।

क्यों होती है कैल्शियम की कमी ?

. यदि बच्चे ने 1 साल से कम उम्र तक मां का दूध न पीया हो।

. विटामिन-डी की कमी से भी कैल्शियम की कमी होती है।

. कुछ हार्मोन जैसे शरीर में कैल्शियम की कमी की वजह बनते हैं।

. पैराथायराइड ग्लैंड के कम विकसित होने से यह समस्या हो सकती है।

. जन्म देते समय यदि मां को डायबिटीज हो तो बच्चे में कैल्शियम की कमी हो सकती है।

. जिजॉर्ज सिंड्रोम नाम के जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण बच्चों में कैल्शियम की कमी हो सकती है।

कैसे करें पूरी ?

. बच्चों के शरीर में से कैल्शियम की कमी पूरी करने के लिए उन्हें दूध से बनी चीजें दें। इसके अलावा सोया से बनी चीजें, फिश बोन, बादाम, स्वीट पौटेटो, तरह-तरह की दालें, बीन्स, ब्रोकली, हरी मटर को शामिल करें।

. बच्चों को रोजाना 15 मिनट सुबह और शाम को धूप जरुर दिलवाएं।

. डॉक्टर की सलाह पर उन्हें विटामिन-डी और कैल्शियम सीरप दें।

वक्त पर पकड़ना है काला मोतिया तो एक बार करें ये काम, पॉल्यूशन का जंजाल होगा खत्म

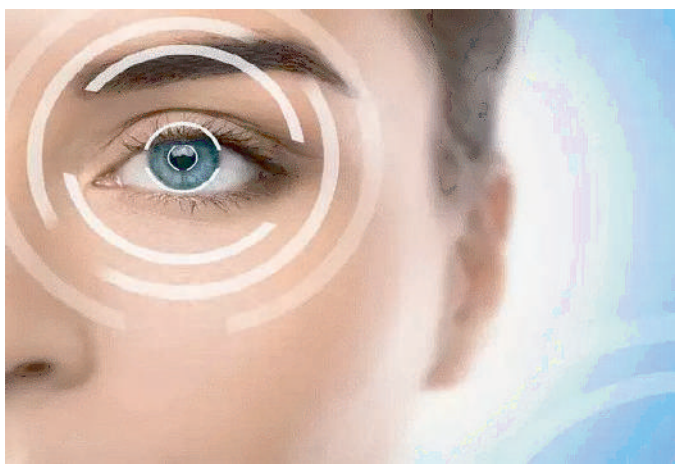

पॉल्यूशन के कारण लोगों को आंखों में जलन, एलर्जी और गले में खराश जैसी परेशानियां हो रही हैं। इससे बचने के लिए विशेष टिप्स दिए गए हैं। आंखों की जांच और डाइलेट करने से आंखों की परेशानियों को समझना आसान होता है। मोबाइल का अधिक इस्तेमाल मायोपिया को बढ़ावा देता है।

पॉल्यूशन ने अपना जोर लगाया हुआ है। लोगों को इस वजह से आंखों में जलन, सांसों की परेशानी, एलर्जी की शिकायत, गले में खराश समेत तमाम तरह की परेशानियों ने घेर रखा है। साथ ही मौसम बदल रहा है और त्योहारों का सीजन भी चल रहा है।

ऐसे में इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं सेहतमंद बने रहने के लिए बेस्ट टिप्स। इन्हें अपनाकर आप खुद को अच्छी सेहत का तोहफा दे सकते हैं।

1. साल में एक बार आई चेकअप

साल में एक बार आंखों की जांच होनी चाहिए, वह भी आंखों को डाइलेट करके। आजकल कंप्यूटर के माध्यम से टेस्टिंग होती है। लेकिन आंखों की अंदरूनी परेशानी का पता लगाने के लिए डाइलेट करने के खास लिक्विड (Tropicamide, Phenylephrine Hydrochloride) की चंद बूंदें आंखों में डाली जाती हैं।

इससे डॉक्टर को आंखों के भीतरी हिस्से, नसें आदि अच्छी तरह दिख जाती हैं। इससे आंखों की परेशानियों को समझना आसान हो जाता है। इस जांच का चलन ज्यादातर शुगर पेशेंट्स और उम्र से जुड़ी परेशानियों में होता है।

फिर भी इस तरह की जांच सभी के लिए होनी चाहिए। 40 साल की उम्र के बाद हर साल आंखों का प्रेशर जरूर चेक कराएं। इससे काला मोतिया वक्त पर पकड़ में आ जाता है।

2. मोबाइल से दूरी

मोबाइल की जरूरत सभी को है। काफी संख्या में बच्चे, बड़े, बुजुर्ग ऐसे हैं, जिनकी यह जरूरत लत बन गई है। लेकिन 6 से 13 साल तक के बच्चों के लिए मोबाइल बड़ी परेशानी पैदा कर रहा है। इससे मायोपिया हो रहा है।

इसमें दूर की निगाह कमजोर हो जाती है। किसी शख्स को 6 फुट की दूरी पर मौजूद कोई भी ऑब्जेक्ट साफ दिखाई न दे तो इसका मतलब है कि वह मायोपिया का शिकार हो सकता है।

ज्यादातर बच्चे मायोपिया वाले ही होते हैं। आम रुटीन में हम एक मिनट में 20 से 25 बार पलकों को झपकाते हैं, लेकिन स्क्रीन देखते समय यह महज 5 से 7 बार रह जाती है।

3. 20:20:20 फॉर्मूला

अगर कोई शख्स किसी से बात कर रहा हो, कहीं जा रहा हो तो वह स्वाभाविक तौर पर कभी नजदीक तो कभी दूर देखता रहता है। लगातार नजदीक देखने का मसला नहीं बनता। लेकिन जब कोई शख्स लगातार मोबाइल या लैपटॉप आदि की स्क्रीन को देखता रहता है तो 'दूरदर्शन' की जरूरत होती है। इसलिए ऐसे शख्स को 20:20:20 फॉर्मूले पर अमल करना जरूरी है यानी हर 20 मिनट बाद 20 बार पलकें झपकना, फिर लगातार 20 सेकंड तक 20 फुट या इससे दूर देखना चाहिए।

इससे आंखों को आराम मिलता है। साथ ही ड्राइ आंखों की परेशानी भी कम होती है। इसके अलावा स्क्रीन पर काम करते हुए बार-बार पलकें झपकाएं। याद रखें, हर 5 सेकंड में एक बार पलकें झपकनी चाहिए।

क्या रात में नहीं सोते आपके बच्चे तो पैरेंट्स अपनाएं ये तरीके

बच्चों के स्वास्थ्य का यदि ध्यान न रखा जाए तो वह बीमार हो जाते हैं। बच्चे हो या बड़े सभी के स्वस्थ शरीर के लिए नींद पूरी होना जरुरी है। ऐसे में यदि आपका बच्चा भी अच्छे से नहीं सोना या बिना नींद पूरे किए उठ जाते हैं तो इसका खराब असर उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। कई पेरेंट्स इस बात से परेशान रहते हैं कि उनका बच्चा रात में अच्छी तरह से नहीं सोता और चिड़चिड़ा हो जाता है। ऐसे में आपकी यह परेशानी दूर करते हुए आज आपको कुछ ऐसे टिप्स बताते हैं जिनके जरिए आप बच्चे की स्लीपिंग क्वालिटी सुधार सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे.....

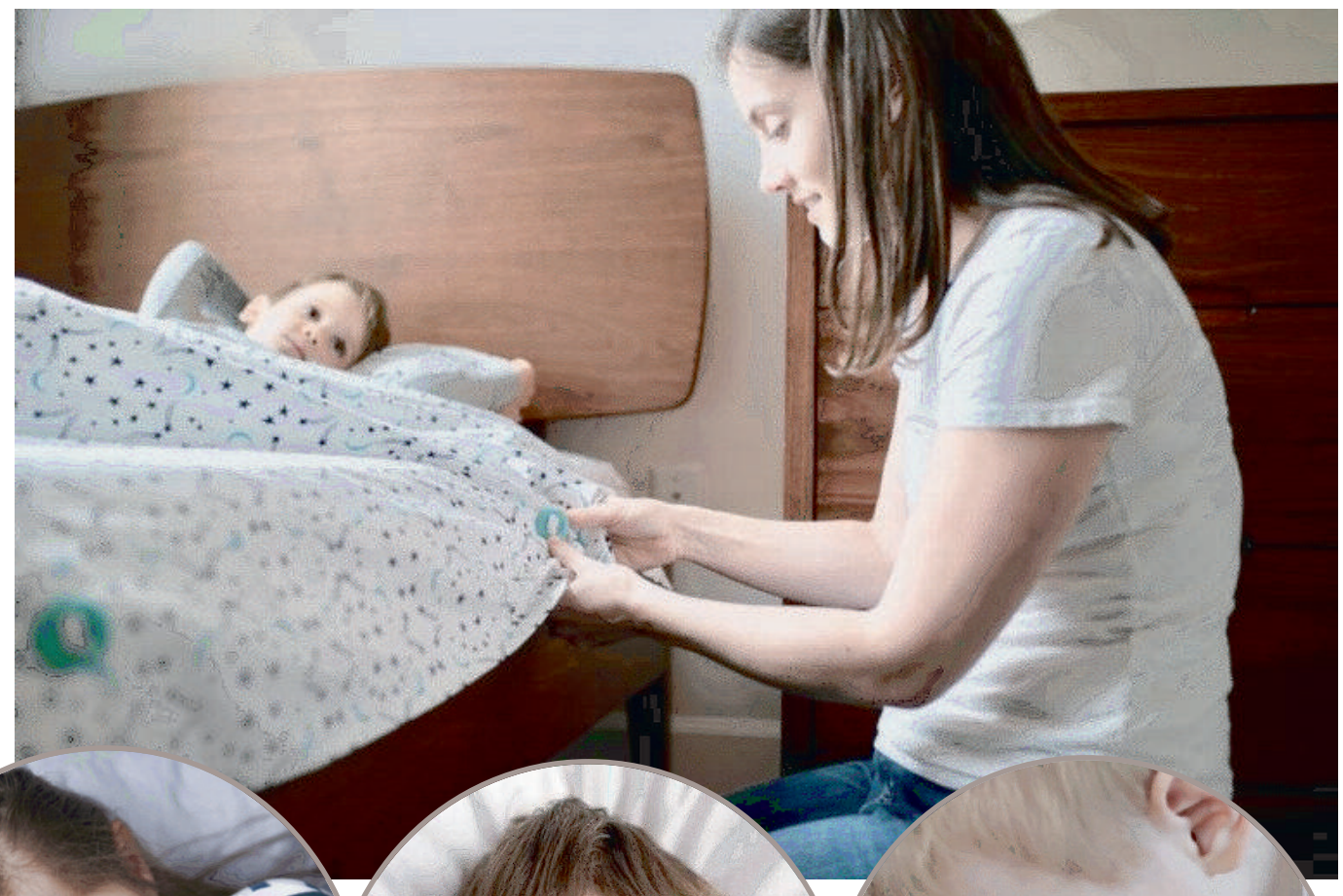

बच्चे हो या फिर बड़े सभी को सोने के लिए एक कंफर्टेबल बिस्तर की जरुरत होती है ऐसे में यदि आप अपने बच्चे के लिए सही बिस्तर का चुनाव करें जिस पर उसे बेहतर नींद आई। कई बार माता-पिता बच्चे के लिए बेहद मुलायम और गद्दे में स्प्रिंग वाले बिस्तर बनाव लेते हैं जो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद साबित नहीं होते।

बच्चों को डालें योग की आदत

रोज सुबह उठने के बाद आप बच्चों को एक्सरसाइज और योग करने की आदत डालें। इसके अलावा उन्हें सुबह की रोशनी में पार्क लेकर जाएं और वहां पर उनके साथ समय बिताएं। ऐसा करने से बच्चे चिड़चिड़े नहीं होंगे और उन्हें नींद भी अच्छी आएगी।

एक समय रखें

बच्चे के सोने और जागने का एक समय रखें। इस बात का भी ध्यान रखें कि आपका बच्चा तय समय पर रोजाना सोए और जागे। यदि आपके बच्चे के सोने और जागने का समय फिक्स हो जाएगा तो इससे उसकी बॉडी भी क्लॉक के हिसाब से काम करेगी। इस तरीके से बच्चों को रोज नींद भी अच्छी आएगी।

स्मार्टफोन, टैबलेट से रखें दूर

बच्चों को रात के समय आप स्मार्टफोन, टैबलेट और टीवी से भी दूर ही रखें। इनका ज्यादा इस्तेमाल करनेसे भी बच्चों को रात में अच्छी नींद नहीं आती। ऐसे में बच्चों को आप किताब पढ़कर सोने की डालें। आप चाहें तो खुद ही किताब पढ़कर बच्चों को सुना सकते हैं। इससे उनकी नींद इंप्रूव होगी।

इस बात का भी रखें ध्यान

जब भी बच्चा सोने के लिए जाए तो किसी भी तरह का शोर न करें। शोर होने से भी बच्चे का मन बाकी कामों में लगेगा और उसे नींद अच्छी नहीं आएगी। यदि आप चाहते हैं बच्चों को सुकून भरी नींद आए तो रात के समय कमरे में कम रोशनी रखें।

जीटीबी अस्पताल मर्डर केस में डाक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की हडताल के बाद एक्शन में प्रशासन

परिवहन विशेष न्यूज

एसडी सेठी। दिल्ली के गुरूतेग बहादुर अस्पताल (जीटीबी) के वार्ड में संडे के दिन शाम 4:00 बजे मरीज रियाजुद्दीन की गोली मार कर हत्या कर दी गई। उस वक्त वार्ड के डॉक्टर स्टाफ भी मौजूद थे। सरेआम अस्पताल के वार्ड में एडमिट मरीज के मर्डर से गुस्साए रेजिडेंट डॉक्टर और नर्सिंग कर्मचारियों ने अस्पताल की सिक्योरिटीज को लेकर हडताल कर दी थी। दो दिन तक चली हडताल के बाद अस्पताल के आलाधिकारियों को होश आया, और आनन फानन में मेडिकल डायरेक्टर डॉ.अस्मिता हडताली कर्मचारियों से मिलने अस्पताल पहुंची। उनके साथ स्पेशल सेकेट्री दानिश अशरफ समेत पुलिस के आलाधिकारी भी अस्पताल मौजूद थे। उन्होंने हडताल स्टाफ के नेताओ के साथ बैठक की। बैठक में शामिल नर्सेज एसोसिएशन और जीटीबी अस्पताल के प्रेसीडेंट जितेंद्र कुमार के मुताबिक हमारी सिक्योरिटीज से संबंधित तमाम मांगों को मान लिया गया है। बैठक में सिक्योरिटीज ऐजेंसी की पोल खुल क गई। अस्पताल अधिकारियों को मुताबिक एजेंसी के एग्रीमेंट के अनुसार करीबन 33 प्रतिशत एक्स सर्विसमैन गार्ड रखने थे,,लेकिन एक भी ऐसा गार्ड नहीं रखा गया है। फैंसले के मुताबिक अब सिक्योरिटीज स्टाफ के पास वॉकी -टॉकी और हथियार से लैस गार्ड, रहेगे। साथ ही पुलिस पैट्रोलिंग के तहत अस्पताल के गेट पर पीसीआर वैन भी खडी रहेगी। इन तमाम सिक्योरिटीज को लेकर फिलहाल अस्पताल प्रशासन एक्शन मोड पर आ गया है। 32 घंटे बाद अब ओपीडी समेत तमाम मेडिकल कारवाई शुरू हो गई है। उल्लेखनीय है कि रविवार को गैंगवार के तहत अस्पताल के वार्ड के अंदर वसीम की जगह किसी अन्य मरीज रियाजुद्दीन 32 साल की गलती से गोली मार कर हत्या कर दी थी। दरअसल समीर की साजिश विफल हुई तो मुंडा-5, के जरिये अस्पताल में मर्डर की रची गई थी साजिश। पुलिस के मुताबिक इस हत्या कांड के आरोपियों जिनमें फैज अहमद और फरहान को पकड लिया गया है। अब जीटीबी अस्पताल की करीब 32 घंटे के बाद कर्मचारियों की हडताल खत्म हो गई है।

भाजपा के सातों सांसदों ने 11 साल में कोई काम नहीं किया और अब ये दिल्ली को तोड़कर बर्बाद करने में लगे हैं- दुर्गेश पाठक

सुषमा रानी

नई दिल्ली। भाजपा की केंद्र सरकार की एजेंसियों द्वारा दिल्ली की झुग्गियों में तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू करने पर आम आदमी पार्टी ने कड़ी आपत्ति जताई है। ''आप'' के वरिष्ठ नेता एवं विधायक दुर्गेश पाठक ने कहा कि दिल्ली में 2014 से सातों सांसद भाजपा के हैं। इन 11 सालों में इन्होंने कोई काम नहीं किया है और अब ये लोग दिल्ली को तोड़कर बर्बाद करने में लगे हुए हैं। भाजपा की केंद्र सरकार की एजेंसी रेलवे ने पटेल नगर व बरार स्क्वायर की हजारों झुग्गियां तोड़ने का नोटिस लगाया है, लेकिन वहां की भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज प्रभावित लोगों के फोन तक नहीं उठा रही हैं। कुछ दिन पहले, डीडीए ने चांदनी चौक इलाके में कई झुग्गियों को तोड़ दिया, लेकिन स्थानीय सांसद प्रवीण खंडेलवाल का कोइ अतापता नहीं है। इन दोनों कार्रवाइयों में भाजपा सांसदों की चुप्पी यह बता रही है कि इस तोड़तोड़ की कार्रवाई में इनका पूरा समर्थन है। उन्होंने कहा, एक तरफ भाजपा व उसके सांसद दिल्ली की झुग्गियां तुड़वा कर लोगों को बेघर करना चाहते हैं तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी लोगों को कानूनी मदद दे रही है।

आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं विधायक दुर्गेश पाठक ने बुधवार को पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर कहा कि दिल्ली की जनता ने पिछले 11 साल से भारी बहुमत देकर भाजपा के सातों सांसदों को जिताया है। लेकिन इतने सालों बाद भी इनके पास अपने कोई काम बताने के लिए नहीं है। रिपोर्ट तो ये भी है कि इन सांसदों ने अपनी सांसद निधि भी खर्च नहीं की है। 2014 से लगातार दिल्ली में भाजपा के सातों सांसद चुन कर आ रहे हैं। लेकिन ये ढेले भर का काम नहीं करते और न ही किसी से मिलते हैं। ये चुनाव जीतते ही राजाओं की तरह इधर-उधर घूमने लग जाते हैं या टीवी पर उल्टे-सीधे बयान देते हैं, लेकिन जमीन पर कोई काम नहीं करते। दिल्ली का एक भी नागरिक ये नहीं बता सकता कि भाजपा के सांसदों ने इतने सालों में क्या काम किया है।

उन्होंने कहा कि जनता के लिए काम न करना तो भाजपा की हमेशा से आदत रही है, लेकिन अब इनके सांसद दिल्ली को बड़े स्तर पर बर्बाद करने पर उतर गए हैं। पिछले एक हफ्ते में दिल्ली के अंदर दो बड़ी घटनाएं घटीं। इसमें पहली घटना केंद्र की भाजपा सरकार और उनके सांसदों द्वारा की गई। केंद्र सरकार के तहत आने वाले डीडीए ने चांदनी चौक में बड़े स्तर तोड़फोड़ की है। लोग 70-80 वर्षों से उस इलाके में रह रहे थे। ऐसा लगता है कि भाजपा के सांसदों के निर्देश पर ये किया गया। क्योंकि पिछले 5 दिनों से चांदनी चौक के सांसद प्रवीण खंडेलवाल एक बार भी वहां नहीं गए। लोगों ने उन्हें बार-बार फोन करने की कोशिश की, लेकिन उनका स्टाफ कह रहा है कि वो बाहर गए हैं। इन सांसदों ने 11 साल से कोई काम नहीं किया और अब दिल्ली को तोड़ने में लगे हुए हैं। इस बीच भाजपा के सांसद प्रवीण खंडेलवाल का कोई अता-पता नहीं है, वो किसी से बात नहीं कर रहे हैं। डीडीए केंद्र सरकार के अधीन है। उनके निर्देश के बिना ये होना संभव नहीं है।

उन्होंने दूसरी बड़ी घटना का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के अधीन भारतीय रेलवे ने पटेल नगर और बरार स्कावयर के अंदर कई किलोमीटर तक हजारों झुग्गियों को तोड़ने का नोटिस लगाया है। नोटिस में लिखा

है कि 22 जुलाई से इन झुग्गियों को तोड़ने का काम शुरू हो जाएगा। ये नोटिस लगे 5 से 6 दिन हो चुके हैं। ये इलाके बांसूरी स्वराज के लोकसभा क्षेत्र में आते हैं, वो नई दिल्ली सीट से यहां की सांसद हैं। लेकिन उन्होंने एक बार भी इन इलाकों का दौरा नहीं किया, लोगों की समस्या नहीं सुनी। उन्होंने एक बार भी रेलवे और अन्य विभागों से बातचीत करके यह कोशिश नहीं की कि जिससे ये झुग्गियां टूटने से बच जाएं। इससे पूरी तरह स्पष्ट है कि ये चीजें उनकी जानकारी में हो रही हैं और सबकुछ जानते हुए भी वो कोई कार्रवाई नहीं कर रही हैं। जबकि अगर वो रेलवे विभाग को एक फोन कर दें तो लोगों का घर टूटने से बच सकता है। लेकिन पिछले 5 दिनों में उन्होंने एक बार भी वहां जाकर लोगों से मिलने की कोशिश नहीं की। लोगों ने उन्हें कई बार फोन करने की कोशिश की लेकिन कभी भी उनका फोन नहीं लगता है।

उन्होंने ने कहा कि 11 साल से भाजपा के सातों सांसद दिल्ली पर राज कर रहे हैं। डीडीए और रेलवे जैसे हजारों विभाग इनके अधीन आते हैं। पहले ये लोग कोई काम नहीं करते थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने विभागों को ये निर्देश दिया है कि दिल्ली को पूरी तरह बर्बाद कर दो। इसमें पटेल नगर से बरार स्कावयर के लोहामंडी, बुद्ध नगर और इंदरपुरी जैसे इलाके शामिल हैं। यहां भारतीय रेलवे द्वारा ये नोटिस चिपकाए गए हैं। 5 से 6 दिन हो गए लेकिन अभी तक किसी सांसद ने किसी की खबर लेने के लिए नहीं गया। वहीं, आम आदमी पार्टी इन दोनों मामलों में वहां के लोगों को लीगल मदद दे रही है। भाजपा ने पिछले 11 सालों से केवल दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया है। महीने-दो महीने में जब इनकी नींद खुलती है तो किसी क्षेत्र का दौरा करते हैं और वहां की तस्वीरें खींचकर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। इसके अलावा इनके पास और कोई काम नहीं है।

उन्होंने कहा कि भाजपा सांसद दिल्लीवालों के खिलाफ काम करना बंद कर दें। आप लोगों से उनका घर छीन रहे हो, इसे बंद कर दो। बांसूरी स्वराज और प्रवीण खंडेलवाल के अधीन रेलवे और डीडीए आता है। ये दोनों इन विभागों को हेड करते हैं, क्योंकि ये दोनों विभाग केंद्र सरकार के अधीन हैं। लेकिन फिर भी ये कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इनकी ये चुप्पी मानी जाए कि ये पर्दे के पीछे से इन विभागों को लोगों के घर गिराने के आदेश दे रहे हैं। दिल्ली के लोगों ने आपको जरूर जिताया है लेकिन ऐसा ही चलता रहा तो आप कब उनकी नजरों से उतर जाएंगे पता भी नहीं चलेगा।

मुहर्रम: दिल्ली में शियाओ ने निकाले ताजिये मनाया शोक, दिल्ली में 2 दिन निकलेगा मुहर्रम का जुलूस

परिवहन विशेष। एसडी सेठी। 1400 साल पहले मुहर्रम के महीने की 10 तारीख को ही पैगंबर मोहम्मद के नाती इमाम हुसैन को शहीद किया गया था। उसी गम में मुहर्रम की 10 तारीख को ताजिया निकाले जाते है। मुहर्रम की तारीख को रोज-ए-आशुरा कहा जाता है।इसी कडी में आज बुद्धवार को शिया समुदाय के लोगों ने काले कपडे पहन कर मातम किया और मजलिस पढा। दिल्ली की जमा मस्जिद से लेकर कई मुस्लिम बाहुल इलाकों में ताजिये निकाले गये। दिल्ली में 2 दिन तक निकलेगा मुहर्रम का जुलूस। ताजियों के साथ चल रहे काले कपडों में शिआओ ने छाती पीट कर पैगम्बर मोहम्मद के नाती की शाहादत पर मातम मनाया। दिल्ली के विजय विहार रोहिणी इलाके में ताजिया निकाले गए। ताजिया के साथ मुस्लिम शिया सामुदाय का हुजूम चल रहा था।काले कपडे पहने युवा- प्रोढों ने तलवार बाजी, और लाठियों के करतब दिखाए। इस मौके पर दिल्ली पुलिस द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मुस्लिम युवाओ द्वारा छाती पीट-पीट के दौरान नारे लगा रहे थे। या हुसैन हम न थे। लेकिन उग्र होते युवाओ के साथ पुलिस का भारी बंदोबस्त था। ताजिया निकालने के बाद तमाम ताजियों को कर्बला में दफना दिया गया।

व्यापारी संगठनों की मांग पर उद्योग मंत्री सौरभ भारद्वाज ने जताई सहमति

सुषमा रानी

नई दिल्ली। दिल्ली में औद्योगिक क्षेत्रों के विकास और रखरखाव को लेकर दिल्ली सरकार ने कमर कस ली है।

इस सम्बंध में आज उद्योग मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सचिवालय में दिल्ली के 27 अलग अलग औद्योगिक क्षेत्रों के फैक्ट्री मालिकों की एसोसिएशन के साथ मुलाकात की। मीटिंग में मंत्री सौरभ भारद्वाज और व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ DSIIDC विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

मीटिंग के दौरान व्यापारिक संगठनों से बात करते हुए उद्योग मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, कि दिल्ली सरकार 27 अनप्लान्ड इंडस्ट्रियल एरिया के विकास और रखरखाव को लेकर बेहद गंभीर है, और पिछले लंबे समय से व्यापारिक संगठनों के साथ मिलकर इन क्षेत्रों के विकास के लिए काम कर रही है और इन क्षेत्र के कायाकल्प को लेकर एक स्कीम लेकर आई है I इस स्कीम के तहत औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए जो भी लेआउट प्लान में खर्च होगा,

उस खर्च का 90% हिस्सा दिल्ली सरकार खर्च कर रही है और 10% हिस्सा फैक्ट्री मालिक वहन कर रहे हैं, ताकि विकास कार्य में सरकार के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्र के व्यापारिक संगठनों की भी जिम्मेदारी तय हो सके I

मीटिंग में शामिल व्यापारियों और उद्यमियों के शीर्ष संगठन सीटीआई के चेयरमैन बृजेश गोयल ने बैठक के दौरान उद्योग मंत्री सौरभ भारद्वाज से कहा, कि दिल्ली में 29 ऑथोराइज्ड इंडस्ट्रियल एरिया हैं, जबकि 27 अनप्लान्ड इंडस्ट्रियल एरिया हैं, बृजेश गोयल ने मीटिंग के दौरान उद्योग मंत्री सौरभ भारद्वाज से सभी व्यापारिक संगठनों की ओर से अनुरोध करते हुए कहा, कि दिल्ली में 27 अनप्लान्ड इंडस्ट्रियल एरिया हैं, और यहां के सभी फैक्ट्री मालिकों की दिल्ली सरकार से गुजारिश है, कि एमसीडी में जो नक्शे पास कराए जाएंगे, उसकी फीस काफी ज्यादा है, तो सभी व्यापरियों का आप से अनुरोध है, कि एमसीडी नक्शे पास कराने का खर्च भी स्कीम के अनुसार ही होना चाहिए।

व्यापारियों की इस मांग पर मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सहमति जताई और अधिकारियों को निर्देश दिया कि सरकार की स्कीम के अनुसार ही नक्शे पास करने की फीस को लेकर पालिसी पर विचार हो।

मीटिंग में शामिल दिल्ली मैन्युफैक्चरिंग फेडरेशन के अध्यक्ष विजय विरमानी ने दिल्ली सरकार की स्कीम का स्वागत करते हुए कहा, कि पिछले 30 सालों में पहली बार किसी सरकार ने व्यापरियों की सुध ली है I उन्होंने कहा कि डाबड़ी, ख्याला, हस्तसाल, नंगली सकरावती, नवादा, पीरागढ़ी, रिठाला, मंडोली, हैदरपुर, करावल नगर, शालामार गांव, समयपुर बादली, लिबासपुर, टीकरी कलां आदि औद्योगिक क्षेत्रों में छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं और इन क्षेत्रों में मध्यम वर्गीय व्यापारी अपना व्यापार चलाते हैं I इन औद्योगिक क्षेत्र में लाखों की संख्या में लोग काम करते हैं I इन छोटे-छोटे औद्योगिक क्षेत्र से लाखों लोगों का परिवार चलता है और इन लाखों लोगों की जिंदगी को सरल और सुगम बनाने की दिशा में दिल्ली कि केजरीवाल सरकार कि यह पहल बेहद ही सराहनीय है I उन्होंने कहा कि इन औद्योगिक क्षेत्र के कायाकल्प होने से न केवल व्यापारी वर्ग को ही लाभ होगा, बल्कि इन क्षेत्रों में उद्योगों को और अधिक बढ़ावा मिलेगा, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, साथ ही साथ दिल्ली की अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा।

दिल्ली को विश्व धरोहर घोषित करने का अभी भी इंतजार, भारत के 57 स्मारक हैं विचाराधीन सूची में शामिल

परिवहन विशेष न्यूज

विश्व धरोहर समिति की 21 जुलाई से दिल्ली में होने जा रही है। इस दौरान भारत के कई स्मारकों को विश्व धरोहर घोषित किए जाने प्रस्ताव दिया जाना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली भी यूनेस्को की विश्व धरोहरों की सूची में शामिल होने का इंतजार है। यूनेस्को ने इसके लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी उनकी टीम ने उस समय दिल्ली का दौरा किया था।

नई दिल्ली। यूनेस्को की विचाराधीन सूची में 12 साल बाद भी दिल्ली को विश्व धरोहर (World Heritage) घोषित करने का प्रस्ताव शामिल है। वर्ष 2012 में पहली बार दिल्ली सरकार की ओर से यह प्रस्ताव भेजा गया था।

उस समय की मनमोहन सिंह सरकार ने उस प्रस्ताव को यूनेस्को के पास भेज दिया था। बाद में विकास कार्य बाधित होने का तर्क देकर केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने को सहमति नहीं दी।

भारत के 57 स्मारक विचाराधीन सूची में शामिल

बता दें कि यूनेस्को की विचाराधीन सूची में है भारत के 57 स्मारक शामिल हैं। उनमें अंडमान का सेलुलर जेल, बुरहानपुर का खूनी भंडारा, ग्वालियर का किला, कश्मीर का मुगल गार्डन, अमृतसर का श्री हरिमंदिर साहिब व वाराणसी के सारनाथ सहित ऐतिहासिक शहर दिल्ली और दिल्ली का कमल मंदिर भी आदि शामिल है।

दिल्ली के इन इलाकों को शामिल करने की मांग

ऐतिहासिक दिल्ली की बात करें तो इसके लिए पहली बार 2012 में यूनेस्को में प्रस्ताव भेजा गया था। उस समय पुरानी दिल्ली यानी शाहजहानाबाद, निजामुद्दीन क्षेत्र, महरौली और लुटियंस दिल्ली इलाके के आधार पर दिल्ली को विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने के लिए प्रस्तावित किया गया था।

यूनेस्को ने इसके लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी, उनकी टीम ने उस समय दिल्ली का दौरा किया था। यूनेस्को ने दिल्ली को लेकर कई तरह की जानकारियां मांगी थीं, जिन्हें उपलब्ध कराने के बाद 2015 में चार की जगह दो इलाकों को ही प्रस्ताव में रखा था।

पुरानी और नई दिल्ली पर था ज्यादा फोकस

इसमें शाहजहानाबाद यानी पुरानी दिल्ली और लुटियंस दिल्ली यानी नई दिल्ली शामिल था। ये दो ऐसे इलाके थे, जहां पर दिल्ली को लेकर अधिक फोकस रहा था और दोनों के समय के निर्माण और संस्कृति भी मौजूद है।

इसमें शाहजहानाबाद को शाहजहां ने अपनी राजधानी बनाया था और बाद में अंग्रेजों ने 1911 में दिल्ली को राजधानी घोषित करने के बाद लुटियंस दिल्ली को बसाया था। जिसमें आज भी कनॉट प्लेस जैसी इमारतें उपलब्ध हैं। दिल्ली अगर विश्व धरोहर बनती तो निर्माण से संबंधित नियम इन्हीं इलाकों पर लागू होते।

शहर को विश्व धरोहर घोषित होने पर ये नहीं होते काम

किसी भी तरह के निर्माण और मरम्मत के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से अनुमति लेनी होती। इलाके की ऐतिहासिकता प्रभावित करने वाले निर्माण पर प्रतिबंध रहता।

शादी के बाद महिलाएं अपने हुनर से कमाई कर सकती हैं

विजय गर्ग

शादी के बाद प्रोफेशन चुनना एक महिला के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला होता है, जो उसके जीवन में कई बदलाव ला सकता है। शिक्षित और कम शिक्षित दोनों महिलाओं के लिए, यह विकल्प व्यक्तिगत कौशल, झुकाव और जीवन स्थिति के आधार पर किया जाना चाहिए। हालाँकि कुछ पेशे दोनों प्रकार की महिलाओं के लिए उपयुक्त हो सकते हैं, लेकिन शादी के बाद महिलाएँ आत्मनिर्भर हो जाती हैं, अपने कौशल से कमाई कर सकती हैं। शिक्षित महिलाओं के लिए व्यवसाय शिक्षक दुनिया भर मेंशिक्षण सबसे अच्छा क्षेत्र माना जाता है। शिक्षक के रूप में महिलाएं छात्रों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, उन्हें ज्ञान का मार्ग दिखाती हैं और सफलता की मंजिल तक पहुंचने में मदद करती हैं। एक शिक्षक का शेड्यूल अधिकतर निश्चित होता है, जो परिवार के साथ समय बिताने के लिए सुविधाजनक होता है। छुट्टियों की व्यवस्था मिलने से पारिवारिक जीवन और व्यक्तिगत हितों को आगे बढ़ाने का अवसर मिलता है। इस प्रकार, शिक्षक का पेशा शिक्षित महिलाओं के लिए एक उपयुक्त और समझदार विकल्प है, जिससे न केवल आर्थिक स्थिति में सुधार होता है।इससे समाज में मान-सम्मान भी मिलता है। इस पेशे की खास बात यह है कि इसमें जहां अच्छी सैलरी मिल रही है, वहीं समाज से सम्मान भी मिलता है। चिकित्सक चिकित्सा पेशा शिक्षित महिलाओं के लिए भी उपयुक्त है, खासकर यदि वे चिकित्सा क्षेत्र में रुचि रखती हों। डॉक्टर बनने के लिए कड़ी मेहनत और पढ़ाई की जरूरत होती है। महिलाओं को स्त्री रोग, बाल रोग एवं अन्य क्षेत्रों में नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। अभियांत्रिकी शिक्षित महिलाओं के लिए इंजीनियरिंग भी एक अच्छा विकल्प है। इंजीनियरिंग के कई क्षेत्र हैं जैसे सिविल, मैकेनिकल,इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर विज्ञान, आदि। महिलाओं को इन क्षेत्रों में करियर के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। वकील कानून और न्याय के क्षेत्र में महिलाएं वकील बन सकती हैं या जज भी बन सकती हैं। यह क्षेत्र नैतिकता और सच्चाई के लिए जाना जाता है, जिससे समाज में मान-सम्मान मिलता है। एमबीए प्रोफेशन एमबीए करने के बाद महिलाएं बिजनेस मैनेजमेंट, फाइनेंस, मार्केटिंग आदि क्षेत्रों में काम कर सकती हैं। व्यवसाय के क्षेत्र में उच्च पदों तक पहुंचने के लिए यह एक अच्छा पेशा है। कम पढ़ी-लिखी महिलाओं के लिए व्यवसाय सिलाई-कढ़ाई सिलाई और कढ़ाई कंपनीकम पढ़ी-लिखी महिलाओं के लिए एम एक अच्छा विकल्प है। वे घर पर रहकर भी यह काम कर सकते हैं और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में योगदान दे सकते हैं। गृह उद्योग घरेलू उद्योग जैसे कागज के पैकेट, खिलौने बनाना, अचार बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना आदि व्यवसाय कम पढ़ी-लिखी महिलाओं के लिए अच्छे अवसर प्रदान कर सकते हैं। वे यह काम घर बैठे भी कर सकते हैं. ब्यूटीशियन कम खर्च में ब्यूटी पार्लर का काम भी एक अच्छा विकल्प है। आजकल हर प्रोग्राम पर इनकी डिमांड रहती है, जिस वजह से यह फील्ड भी उनके लिए अच्छा हैआय का स्रोत हो सकता है. क्रेच सेवा शादी के बाद महिलाएं क्रेच सेवाएं चलाकर घर को आय का जरिया बना सकती हैं। बच्चों की देखभाल के लिए यह एक अच्छा पेशा है। क्षेत्र में काम करो उदाहरण के लिए, खेती, डेयरी, पोल्ट्री फार्म आदि में काम करने से महिलाओं को आय का अच्छा स्रोत मिल सकता है। ये काम उनके जीवन को बेहतर बना सकते हैं और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बना सकते हैं। पेशा चुनते समय महिलाओं को अपनी रुचि, कौशल और जीवन की स्थिति पर विचार करना चाहिए। प्रत्येक महिला की अपनी व्यक्तिगत परिस्थितियाँ और वर्तमान अवसर होते हैंइस बात को ध्यान में रखकर ही सही प्रोफेशन का चुनाव करना चाहिए।

सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य शैक्षिक स्तंभकार मलोट

दर्दनाक हादसा: ग्रेटर नोएडा में पलटी स्कूल बस

बच्चों में मची चीख-पुकार; राहगीरों ने शीशे तोड़कर निकाला बाहर

परिवहन विशेष न्यूज

ग्रेटर नोएडा में बुधवार को दर्दनाक हादसा हो गया। यहां फालेंदा गांव के पास एक स्कूल की बस पलट गई। हादसे के बाद बस में सवार बच्चों में चीख-पुकार मच गई। वहीं मौके पर पहुंचे राहगीरों ने बस के शीशे तोड़कर सभी बच्चों को बाहर निकाला। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। सभी बच्चों को मामूली चोट आई है। जानिए आखिर यह हादसा कैसा हुआ?

ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में रबूपुरा कोतवाली क्षेत्र के फलेंदा गांव के समीप निजी स्कूल बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दौरान बस में सवार छात्र-छात्राओं में चीख-पुकार मच गई।

बताया गया कि इस हादसे में दर्जनों बच्चे घायल हो गए हैं। ग्रामीणों ने बस के शीशे तोड़कर बच्चों को बाहर निकाला। इसके बाद नजदीकी अस्पताल भर्ती कराया। सभी घायल बच्चों का अस्पताल में उपचार चल रहा है।

सभी बच्चों को मामूली चोट आई

Greater Noida Police के अनुसार, सभी बच्चों के मामूली चोट आई है। पुलिस ने हादसे को लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर हादसा कैसा हुआ।

स्कूल की छुट्टी होने के बाद घर जा रहे थे बच्चे

जानकारी के अनुसार, बस रबूपुरा क्षेत्र स्थित लक्ष्मी पब्लिक स्कूल की है। छुट्टी होने के बाद बच्चे स्कूल बस में सवार होकर अपने घर जा रहे थे। फलेंदा गांव के समीप सामने से स्विफ्ट डिजाइर गाड़ी आ गई। उसे बचाने के चक्कर में बस अनियंत्रित होकर पलट गई।

बस में सवार थे 25 बच्चे

हादसे के दौरान बस में 25 बच्चे सवार थे। जिन्हें हल्की-फुल्की चोट आई है। बस पलटने की सूचना पर कई अभिभावक भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सभी बच्चों की स्थिति सामान्य है।

ग्रामीणों ने शीशे तोड़कर निकाला बाहर

बस पलटने के बाद ग्रामीणों ने बस के शीशे तोड़कर छात्रों को बाहर निकाला। इस घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने बताया कि कार को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ है।

फिलहाल राहत की बात यह है कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। पुलिस का कहना है कि अगर शिकायत मिलती है तो आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

विदेश में नौकरी लगवाने के नाम पर करता था ठगी, अब पुलिस के हत्थे चढ़ा; पूछताछ में खुले कई बड़े राज

परिवहन विशेष न्यूज

ग्रुरुग्राम पुलिस ने एक शातिर आरोपित को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से एक मोबाइल और लैपटॉप बरामद किया है। पूछताछ में पता चला कि आरोपित कैसे लोगों से नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करता था। पुलिस उसे रिमांड पर लेकर यह पूछताछ करेगी कि उसके साथ और कौन-कौन शामिल है और वह कब से लोगों के साथ ठगी कर रहा है।

गुरुग्राम। दूसरे देश में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी करने के मामले में साइबर थाना पूर्वी पुलिस ने एक आरोपित को सेक्टर-43 से गिरफ्तार कर लिया। उसकी पहचान मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा निवासी जतिन जोशी के रूप में हुई। एसीपी साइबर क्राइम प्रियांशु दीवान ने बताया कि शिकायत के आधार पर तकनीकी की मदद लेकर आरोपित जतिन को पकड़ा गया। वह फिलहाल सेक्टर-52 के आरडी सिटी में रह रहा था। उसके विरुद्ध संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया है।

इंटरव्यू लेकर भेजता था अपने साथियों के पास

पुलिस पूछताछ में पता चला कि वह एक कंपनी में काम करता था। वह वेबसाइट के माध्यम से नौकरी करने के इच्छुक लोगों का डाटा लेकर उनसे संपर्क करता था। उनको विदेश में नौकरी दिलाने के लिए इंटरव्यू लेकर उनको शॉर्ट लिस्ट कर अपने अन्य साथियों के पास भेजता था।

आरोपित के पास से मोबाइल और लैपटॉप बरामद

इसके बाद उन लोगों से जरूरी कागजात बनवाने के नाम पर पैसे लिए जाते थे। पुलिस टीम ने आरोपित के कब्जे से एक मोबाइल फोन व एक लैपटॉप बरामद किया गया है।

पूछताछ के दौरान खुल सकते हैं बड़े राज

ग्रुरुग्राम पुलिस के अनुसार, उससे रिमांड के दौरान उसके नेटवर्क के बारे में पूछताछ की जाएगी। साथ ही यह भी पता लगाया जाएगा कि वह कब से इस तरह की ठगी की वारदात को अंजाम दे रहा था। कितने लोगों से उसने अब ठगी की है। माना जा रहा है कि पुलिस रिमांड के दौरान शातिर आरोपित गिरोह के कई बड़े राज खोल सकता है।

डीएम को क्या पता, तुम्हारे राशन कार्ड का एड्रेस कहां से ठीक होगा; बुजुर्ग की बात सुन झल्लाया सरकारी अधिकारी

गाजियाबाद के एक बुजुर्ग को राशन कार्ड का एड्रेस बदलवाने के लिए सरकारी कार्यालय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। इसके बावजूद उसकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। राशन कार्ड में पता सही न होने से एक साल से बुजुर्ग को राशन नहीं मिल रहा है। इससे परेशान होकर जब वह जिलाधिकारी के पास समस्या लेकर पहुंचे तो वहां से आश्वासन मिला।

गाजियाबाद। बिना आवेदन के ही गाजियाबाद में रहने वाले एक बुजुर्ग का राशन कार्ड दिल्ली के करावल नगर में ट्रांसफर कर दिया गया। इसकी शिकायत उन्होंने जिलाधिकारी गाजियाबाद से की तो जिलाधिकारी ने उनको जिला पूर्ति विभाग में जाकर एक प्रार्थना पत्र राशन कार्ड को गाजियाबाद में ही दर्ज करने के लिए देने को कहा।

इसके बाद बुजुर्ग जब जिला पूर्ति विभाग के कार्यालय में गए और राशन कार्ड गाजियाबाद में ही दर्ज करने के लिए कहा तो वहां बैठे एक अधिकारी ने कहा कि इसके लिए दिल्ली जाना होगा। बुजुर्ग ने कहा कि डीएम साहब ने तो आपके पास भेजा है और बताया है कि इसकी कार्यालय से पता ठीक हो जाएगा तो झल्लाकर अधिकारी ने कहा कि डीएम को क्या पता, तुम्हारे राशन कार्ड का पता कहां से ठीक होगा?

20 साल से कृष्णा नगर में रहते हैं कालूराम

फिलहाल एक साल से बुजुर्ग को राशन नहीं मिल रहा है, वह गाजियाबाद से दिल्ली तक चक्कर काटने के लिए मजबूर हो रहे हैं। गाजियाबाद के सिकरोड में जन्मे कालूराम पिछले 20 साल से कृष्णा नगर में परिवार के साथ रहते हैं। वह बीएसएनएल से सेवानिवृत कर्मचारी हैं।

उन्होंने बताया कि उनका राशन कार्ड कृष्णा नगर के पते पर बना हुआ थ, जिससे वह राशन ले रहे थे। एक साल पहले उनको राशन डीलर ने राशन देने से मना कर दिया, पूछने पर बताया कि उनका राशन कार्ड दिल्ली के करावल नगर के पते पर ट्रांसफर कर दिया गया है।

बुजुर्ग ने कहा कि वह न तो दिल्ली में रहते हैं न ही दिल्ली में राशन कार्ड ट्रांसफर कराने के लिए आवेदन किया है। बिना आवेदन यह कैसे हो गया तो राशन कार्ड डीलर ने जिला पूर्ति विभाग के कार्यालय जाने को कहा, वह जिला पूर्ति विभाग के कार्यालय गए तो सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद जिलाधिकारी गाजियाबाद से मिले और एक प्रार्थना पत्र दिया।

जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि उनके राशन कार्ड का पता जिला पूर्ति विभाग के अधिकारियों से ठीक कराया जाएगा, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है। जिला पूर्ति विभाग में शिकायत करने पर उनको पता सही कराने के लिए दिल्ली भेजा गया, वह दिल्ली पहुंचे तो वहां पर भी शिकायत का समाधान नहीं हो सका है।

दिल्ली हाट की तर्ज पर बनेगा गुरुग्राम हाट सांझा बाजार, नगर निगम तैयारियों में जुटा

परिवहन विशेष न्यूज

गुरुग्राम हाट बाजार दिल्ली हाट की तर्ज पर गुरुग्राम हाट सांझा बाजार बनाया जाएगा। इससे गुरुग्राम के लोगों को काफी फायदा मिलेगा। साथ ही लोगों के लिए घूमने के लिए नई जगह भी मिलेगी। नगर निगम गुरुग्राम ने सदर बाजार को भी आधुनिक बाजार बनाने की योजना बनाई थी। यहां दिनभर बाजार में अतिक्रमण रहता है। इसको लेकर बैठक में चर्चा की गई।

गुरुग्राम। दिल्ली हाट की तर्ज पर गुरुग्राम हाट सांझा बाजार बनाया जाएगा। इसके लिए गुरुग्राम नगर निगम तैयारी कर रहा है। इस बाजार में दिल्ली हाट की तर्ज पर सभी तरह का सामान उपलब्ध होगा और विक्रेताओं के साथ ग्राहकों को भी सुविधा मिलेगी।

बुधवार को हुई मासिक समीक्षा बैठक में निगमायुक्त डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ ने अधिकारियों को गुरुग्राम हाट बनाने की तैयारी करने और स्थान चिह्नित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा लाल डोरा क्षेत्र में स्वामित्व प्रमाण पत्र देने, तथा स्वच्छ सर्वेक्षण-2024 की तैयारियों को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई।

आधुनिक बाजार बनाने की योजना

बता दें कि नगर निगम गुरुग्राम ने सदर बाजार को भी आधुनिक बाजार बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन फिलहाल यह योजना सिरे नहीं चढ़ी है। सदर बाजार शहर का सबसे पुराना बाजार है। पूरा शहर यहां से खरीदारी करता है, लेकिन सुविधाएं नहीं होने से ग्राहकों के साथ-साथ दुकानदार भी परेशान हैं। दिनभर बाजार में अतिक्रमण रहता है।

गुरुग्राम के लोगों को मिलेगी अच्छी सुविधा

अगर दिल्ली के हाट बाजार की तर्ज पर गुरुग्राम हाट सांझा बाजार बनता है तो इससे लोगों को सुविधाएं मिलेगी। दिल्ली हाट बाजार बिना बिचौलियों के दुकानदारों द्वारा ग्राहकों को सीधे सामान उपलब्ध करवाता है, जिससे ग्राहकों को भी अच्छी गुणवत्ता का सामान कम रेट पर मिल रहा है।

इसके साथ ही एक ही जगह पर हस्तशिल्प से लेकर अन्य घरेलू सामान आसानी से उपलब्ध है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गुरुग्राम में भी हाट बाजार बनाने की जरूरत है।

प्रॉपर्टी टैक्स सेल्फ सर्टिफिकेशन करवाएं

नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ ने कहा कि सभी जोनल टैक्सेशन अधिकारी अपने-अपने जोन में प्रॉपर्टी टैक्स सेल्फ सर्टिफिकेशन कार्य में और अधिक तेजी लाएं, ताकि प्रॉपर्टी टैक्स डाटा जल्द से जल्द पूरी तरह से दुरुस्त हो सके। उन्होंने कहा कि जोनल टैक्सेशन अधिकारी आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों से मिलकर विशेषकर उस प्रतिनिधि को प्रशिक्षित करें, जो आरडब्ल्यूए कार्यालय के सभी कार्य संभाल रहा है क्योंकि उक्त व्यक्ति से उस कॉलोनी, सेक्टर या सोसायटी के सभी प्रॉपर्टी मालिकों का संपर्क रहता है।

दस प्रतिशत छूट मिल रही

निगमायुक्त ने कहा कि 31 जुलाई तक अपने प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करके सरकार द्वारा मौजूदा वित्त वर्ष 2024-25 के प्रॉपर्टी टैक्स में 10 प्रतिशत की दी जा रही छूट का लाभ उठाएं। बैठक में अतिरिक्त आयुक्त डॉ. बलप्रीत सिंह, संयुक्त आयुक्त प्रदीप कुमार, डॉ. नरेश कुमार, सुमन भांखड़ व अखिलेश यादव, डीआरओ विजय यादव सहित जोनल टैक्सेशन अधिकारी तथा नगर परिषद सोहना व पटौदी मंडी व नगर पालिका फरुखनगर के

कॉलोनी में टहल रही महिला से लूटे कुंडल, वारदात को अंजाम देकर भाग गए बदमाश

यूपी के गाजियाबाद जिले में बुधवार सुबह बदमाशों ने एक लूट की वारदात को अंजाम दे डाला। पैदल आए बदमाश ने कॉलोनी में टहल रही महिला से कुंडल लूट लिए और अपने साथियों के साथ मौके से फरार हो गया। लूट की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाश की तलाश शुरू कर दी है।

गाजियाबाद। गाजियाबाद जिले के साहिबाबाद में बदमाशों ने एक लूट की घटना को अंजाम दिया है। बताया गया कि इंदिरापुरम में कॉलोनी में टहल रही महिला से बदमाशों ने कुंडल लूट लिए और मौके से फरार हो गए।

कुंडल लूटकर भाग गए बदमाश

इंदिरापुरम कोतवाली क्षेत्र के अभय खंड में कॉलोनी में टहल रही महिला से पैदल आए बदमाश ने कुंडल लूट लिए। बदमाश बाइक स्टार्ट खड़े अपने साथी के साथ बैठकर मौके से फरार हो गया।

महिला ने शोर मचाया तो भाग गए बदमाश

इस दौरान महिला शोर मचाते हुए बदमाशों के पीछे भागी लेकिन, बदमाश आनन-फानन में मौके से फरार हो गए। बताया गया कि गेट बंद कॉलोनी में यह वारदात बुधवार सुबह हुई।

मुस्लिमों को कूपमंडूक बनाए रखना चाहते हैं गैरभाजपा दल

योगेंद्र योगी

शाह बानो केस में राजीव गांधी की सरकार ने वोट बैंक की खातिर कोर्ट का फैसला बदल दिया था। शाह बानो ने 1978 में इसके खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने अदालत से गुजारिश की कि उनके पति को उन्हें गुजारा भत्ता देने के लिए निर्देश दिया जाए।

गैरभाजपा राजनीतिक दलों में विशेषकर कांग्रेस ने मुस्लिमों के वोट पाने के लिए उनके अधिकारों को लेकर कभी भी पहल नहीं की। यही वजह रही कि देश का मुस्लिम वर्ग विकास की मुख्य धारा में शामिल होने से पिछड़ गया। इतना ही नहीं गैरभाजपा दलों ने जब कभी मुसलमानों की भलाई का मौका आया तब नजरें चुरा ली बल्कि सत्ता में आने पर पुरानी स्थिति बहाल करने तक का वादा किया। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। मुस्लिम महिला को पति से गुजारा भत्ता देने की मांग की याचिका थी। कोर्ट ने कहा सभी महिलाएं सीआरपीसी की धारा 125 की मदद ले सकती हैं। यह कानून सभी धर्म की महिलाओं पर लागू होता है। गुजारे भत्ते के लिए अपने पति के खिलाफ याचिका दायर कर सकती है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टिन गॉर्ज मसीह ने फैसला सुनाया।

इस फैसले को गैरभाजपा दल गले नहीं उतार पा रहे हैं। इसी तरह तीन तलाक के फैसले को लेकर कांग्रेस सहित दूसरों दलों ने विरोध किया था। कांग्रेस ने सत्ता में आने पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए तीन तलाक के फैसले को पलट कर वापस तीन तलाक लागू करने का वादा किया था। इससे पहले शाह बानो पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने कानून में संशोधन करके बदल दिया था। कांग्रेस ने यह सब किया वोट बैंक की खातिर, किन्तु वह भी बच नहीं सका। दूसरे दल मुसलमानों की भलाई की आड़ में अपना उल्लू सीधा करने में ज्यादा आगे निकल गए। गैर कांग्रेस दलों में प्रमुख रूप से पश्चिमी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, उत्तर प्रदेश में समाजवादी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम वोटों की खातिर आतंकवाद के आरोपियों से समझौता तक करने में गुरेज नहीं किया।

शाह बानो केस में राजीव गांधी की सरकार ने वोट बैंक की खातिर कोर्ट का फैसला बदल दिया था। शाह बानो ने 1978 में इसके खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने अदालत से गुजारिश की कि उनके पति को उन्हें गुजारा भत्ता देने के लिए निर्देश दिया जाए। साल 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने शाह बानो के पक्ष में फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद अब्दुल को अपनी तलाकशुदा बीवी को 20,000 रुपए गुजारा भत्ता देने का कहा गया था। समद ने अपनी बीवी को तीन तलाक दिया था। इसके जवाब में तत्कालीन राजीव गांधी की सरकार ने मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 लागू कर दिया। इस अधिनियम ने तलाक के बाद केवल 90 दिनों तक मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं को अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता पाने के अधिकार को प्रतिबंधित कर दिया। इसी तरह मुस्लिमों की आधी आबादी के पक्ष में जब तीन तलाक को निरस्त सुप्रीम कोर्ट द्वारा निरस्त किया गया तब भी गैरभाजपा दलों ने काफी हायतौबा मचाई थी। सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संविधान पीठ ने 22 अगस्त 2017 को अपने फैसले में ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। कोर्ट ने 1400 साल पुरानी प्रथा को असंवैधानिक करार दिया था और सरकार से कानून बनाने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने कानून बनाते हुए एकसाथ तीन बार तलाक बोलकर या लिखकर निकाह खत्म करने को अपराध की श्रेणी में शामिल कर लिया। इस अपराध के लिए अधिकतम तीन साल कैद की सजा का प्रावधान भी है। तीन तलाक के मुद्दे पर गैरभाजपा दलों का असली चेहरा तब सामने आया जब संसद में इसके मामले में कानून पास करने से पहले वोटिंग हुई। गैरभाजपा दल ट्रिपल तलाक के खिलाफ थे, लेकिन राज्यसभा से वोटिंग के पहले भाग गए। इनमें बसपा के 4, सपा के सात, एनसीपी के 2, पीडीपी के 2, कांग्रेस के 5, टीएमसी, वामपंथियों पार्टियों, आरजेडी, डीएमके और वाईएसआर कांग्रेस के एक-एक सांसद अनुपस्थित रहे। बिल को पास कराने के लिए एनडीए को 121 सदस्यों का समर्थन चाहिए था, लेकिन सांसदों की बड़ी संख्या में अनुपस्थिति की वजह से सदन में बीजेपी की स्थिति मजबूत हो गई और वह बिल पास कराने में सफल रही। विपक्ष के भागने की वजह यह रही कि भाजपा इसे मुद्द बना कर मुस्लिम महिलाओं से उनके खिलाफ धरना-प्रदर्शन नहीं करवा दे।

बिल पर बहस के दौरान वाईएसआर कांग्रेस के विजय साई ने कहा कि बिल का मैं 6 कारणों से विरोध करता हूं। लेकिन वोटिंग के दौरान विजय साई सदन में अनुपस्थित थे। बसपा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा का कहना था कि हमारी पार्टी इस बिल के खिलाफ है और इसे सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे नकार दिया है और आप फिर से इसे अस्तित्व में लाना चाहते हैं। इस बिल से महिलाएं सबसे ज्यादा प्रताड़ित होने वाली हैं क्योंकि पुरुष के जेल जाने के बाद महिलाएं भी कहीं की नहीं रह जाएंगी। सरकार ने बच्चों की देखरेख करेगी और न महिलाओं को गुजारा भत्ता देगी, ऐसे में उनका जीवन कैसे चलेगा। तीन तलाक पर इस तरह मुखर होने के बावजूद बसपा का कोई सांसद सदन में उपस्थित नहीं था।

एनसीपी सांसद माजिद मेमन ने भी बिल का विरोध किया। उन्होंने कहा कि कहा कि आप किसी को बगैर अपराध के 3 साल की सजा देने जा रहे हैं, तलाक कहना कोई अपराध नहीं है। जेल में जाने के बाद भी शादी खत्म नहीं होगी और महिला को गुजारा भत्ता के लिए मजिस्ट्रेट के पास जाना होगा। जेल में रह रहा पति कैसे पत्नी को भत्ता दे पाएगा, ऐसे में कानून फेल हो गया। यह बिल पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है। मगर जब बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने के लिए सदन में वोटिंग हो रही थी, उस दौरान एनसीपी प्रमुख शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल उपस्थित नहीं थे। तीन तलाक बिल का विरोध करने वाले एनडीए के सहयोगी दल तो वॉकआउट कर गए जिनमें अन्नाद्रमुक, जेडीयू शामिल हैं। गैर-एनडीए और गैर-यूपीए टीआरएस सदन में गैर मौजूद रही।

कांग्रेस के अल्पसंख्यक महाधिवेशन में महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुष्मिता देव ने कहा था कि अगर हमारी सरकार आई, तो नरेंद्र मोदी सरकार के लाए ट्रिपल तलाक कानून को खत्म कर देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि ये कानून मुस्लिम पुरुषों को जेल में भेजने की एक साजिश है। इस सम्मेलन में कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी समेत अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद थे। लेकिन कोई भी कांग्रेसी नेता एक लफ्ज तक नहीं बोला।

तीन तलाक पर पाबंदी का फैसला हो या मेंटीनेंस पाने का हक, मुस्लिम आधी आबादी लंबे अर्से से अपने अधिकारों के प्रति अंधेरे में रही है। उलेमाओं और मौलवियों ने ऐसे अधिकारों का हमेशा से विरोध किया है। वोट बैंक के लालच में कांग्रेस सहित दूसरे दलों ने हमेशा मुस्लिम महिलाओं को अधिकारों से वंचित करने की पैरवी की है। यदि ये दोनों अधिकार कांग्रेस आजादी के बाद मुस्लिम महिलाओं को कानूनी तौर पर मुहैया करा देती तो आज देश में मुसलमानो के विकास की सूरत अलग होती। किसी भी शिक्षित और जागरुक कौम को आसानी से बरगलाया नहीं जा सकता। गैरभाजपा विपक्षी दलों ने मुसलमानों को जागरुक करने और शिक्षित करने के लिए भी पर्याप्त कदम नहीं उठाए। यहां तक मुसलमानों के खैरख्वाह बनने का दंभ भरने वाले राजनीतिक दलों ने उन्हें राजनीति में पर्याप्त प्रतिनिधित्व तक नहीं दिया। यही वजह रही आजादी के बाद जितनी तरक्की मुसलमानों को करनी चाहिए थी, उसकी तुलना में पिछड़ गए।

- :सौजन्य :-
ईवी ड्राइव द फ्यूचर
EV
Drive the Future

ब्लूस्मार्ट ने जुटाए 24 मिलियन डॉलर; एमएस धोनी ने भी किया निवेश

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। घरेलू इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी ब्लूस्मार्ट ने फंडिंग के एक दौर में 24 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 200 करोड़ रुपये जुटाए हैं। 'प्री-सीरीज बी फंडिंग' दौर में रिस्पॉन्सएबिलिटी इन्वेस्टमेंट्स एजी जैसे मौजूदा निवेशकों के साथ-साथ रीन्यू के चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमंत सिन्हा और एमएस धोनी फैमिली ऑफिस जैसे नए निवेशकों ने भी हिस्सा लिया।

कंपनी के अनुसार, इस फंडिंग से ब्लूस्मार्ट को अपने परिचालन का विस्तार करने और प्रमुख भारतीय शहरों में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और संपत्ति बनाने में मदद मिलेगी। ब्लूस्मार्ट के सह-संस्थापक पुनीत गोयल ने कहा, "24 मिलियन अमरीकी डॉलर की हमारी नवीनतम फंडिंग ई-ट्रांसपोर्ट बेड़े और ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करने की हमारी यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है।"

पूर्व क्रिकेटर एम. एस. धोनी ने कहा, ₹ब्लूस्मार्ट के टिकाऊ व्यापार मॉडल में निवेश करना सिर्फ एक कंपनी का समर्थन करना नहीं है, बल्कि उस बदलाव का हिस्सा बनना है जो परिवहन के भविष्य को आकार दे रहा है।"

रिकॉर्ड बिक्री के बीच लोहिया ईवी अपने इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर पोर्टफोलियो का करेगी विस्तार

परिवहन विशेष न्यूज

भारत में इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं में से एक लोहिया ने अपने नए इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर को लॉन्च करने की घोषणा की है। यह इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर सेगमेंट पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने का प्रतीक है। इस रणनीतिक कदम का उद्देश्य नए और स्थिर समाधानों के साथ ईवी बाज़ार में क्रांति लाना है। कंपनी ने उपभोक्ताओं के विभिन्न वर्गों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ई-रिक्शा और थ्री व्हीलर की एक विस्तृत श्रृंखला तैयार की है।

इन नए मॉडलों को लॉन्च करने के पीछे कंपनी का उद्देश्य अत्यधिक प्रतिस्पर्धी इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर बाजार में पैर जमाना है। यह बाजार काफी बढ़ चुका है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के नवीनतम ग्लोबल ईवी आउटलुक के अनुसार, 2023 में दुनिया भर में बिकने वाले पांच में से एक थ्री-व्हीलर ईवी होगा। 60 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन भारत में ही बेचे गए।

सरकारी समर्थन और सरकारी नीतियों ने भारत को इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर बाजार में चीन से आगे निकलने में मदद की है। आईईए IEA के अनुसार 2023 में 5 लाख 80 हजार से अधिक इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर बेचे गए। इससे लोहिया के लिए इस अवसर को भुनाना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर सेगमेंट में प्राइस वॉर सबसे महत्वपूर्ण कारक है। कंपनी का लक्ष्य गुणवत्ता और प्रदर्शन से समझौता किए बिना उपभोक्ताओं को किफायती समाधान प्रदान करना है।

लोहिया इस महीने के अंत तक एल3 और एल5 दोनों श्रेणियों में बैटरी से चलने वाले ऑटो रिक्शा लॉन्च करेगी। ये मॉडल नए ग्राफिक्स के साथ बहुत आकर्षक दिखते हैं और किफायती कीमतों पर उपलब्ध हैं। इससे उपभोक्ताओं का एक बड़ा वर्ग इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने में सक्षम हो गया है। इसकी प्रतिस्पर्धी कीमतों से इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर बाजार में किफायती और नवीनतम सुविधाओं वाले इलेक्ट्रिक स्कूटरों के एक नए युग की शुरुआत होने की उम्मीद है।

भारत में इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। इसकी वजह उपभोक्ताओं की ओर से स्थिर परिवहन समाधानों की बढ़ती मांग है। जून 2024 में रिटेल सेक्टर में 79,000 से अधिक इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर बेचे गए। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर ने महीने दर महीने 27 प्रतिशत और साल दर साल 17 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। इसके अलावा आईसीआरए ICRA की रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक बाजार में इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर 14 से 16 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है। इन नए मॉडलों के रणनीतिक लॉन्च के साथ लोहिया इस ट्रेंड का पूरा लाभ उठाने की स्थिति में है।

लोहिया के सीईओ आयुष लोहिया ने कहा, "हमारे नए इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर मॉडल का लॉन्च हमारी यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण है। हम स्थायी परिवहन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर क्रांति का नेतृत्व कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर श्रेणी भारत में शहरी परिवहन का भविष्य है, जो उपभोक्ताओं को स्वच्छ पर्यावरण के साथ-साथ आर्थिक लाभ भी पहुंचाती है। हम भारत में सभी के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को सुलभ बनाने और देश में स्वच्छ पर्यावरण की दिशा में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारे द्वारा लॉन्च किए गए नए उत्पाद भारत के उभरते इलेक्ट्रिक वाहन बाजार की विविध आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। कंपनी के प्रयास सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप हैं। सरकार 2030 तक भारत को इलेक्ट्रिक वाहन राष्ट्र बनाना चाहती है।"

आयुष लोहिया ने कहा, "हमारे पास वित्त वर्ष 24-25 में 200 मिलियन रुपये निवेश करने की महत्वाकांक्षी योजना है। हमारा ध्यान अनुसंधान और विकास, बुनियादी ढांचे का विस्तार और बाजार में अपनी जगह बनाने पर है। यह निवेश कंपनी को लगातार नया करने में सक्षम बनाएगा। हम लोगों को अधिक से अधिक उत्पाद पेश करने और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर बाजार में अपनी अग्रणी स्थिति बनाए रखने में सक्षम होंगे।"

आयुष लोहिया ने आगे कहा, "हमारी कुल बिक्री 5,000 यूनिट है, जिसे हम इस साल सभी श्रेणियों में बढ़ाकर 10,000 यूनिट करेंगे।" इन नए मॉडलों के लॉन्च का समर्थन करने और बाजार में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के लिए लोहिया ने अपने डीलर और बिक्री नेटवर्क का काफी विस्तार करने की योजना बनाई है। इस विस्तार योजना से कंपनी के उत्पाद पूरे देश में उपलब्ध होंगे। इससे उपभोक्ताओं को अभिनव और किफायती इलेक्ट्रिक मोबिलिटी समाधानों तक आसान पहुंच मिलेगी।

कंपनी ने इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर की नई रेंज की संभावित बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपने काशीपुर प्लांट में ईवी का उत्पादन बढ़ाने की योजना बनाई है। कंपनी का आधुनिक प्लांट नई तकनीक और बुनियादी ढांचे से लैस है, जो उच्च गुणवत्ता वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के बड़े पैमाने पर उत्पादन को सक्षम करेगा।

अतुल ऑटो लिमिटेड ने जोधपुर में किया अपने नए स्टोर का उद्घाटन

परिवहन विशेष न्यूज

अतुल ऑटो लिमिटेड ने जोधपुर में अपने नए स्टोर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर नए इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर लॉन्च किए गए। अत्याधुनिक वाहन दोहरी बैटरी विकल्प के साथ आते हैं, जो अपनी श्रेणी में पहली बार है और क्रमशः 210 किमी और 180 किमी की प्रभावशाली रेंज प्रदान करते हैं। अतुल एल 5 ईवी सीरीज के वाहन लिक्विड-कूल्ड ऑयल-इमर्स्ड बैटरी से लैस हैं, जो 3 व्हीलर सेगमेंट में सबसे सुरक्षित बैटरियों में से एक है। इस महीने भारत के प्रमुख शहरों में 20 नए स्टोर खोलने की योजना है। इस अवसर पर कंपनी के प्रबंध निदेशक नीरज भाई चंद्रा भी मौजूद थे।

टाटा कर्व को चुनौती देने जल्द आ रही है सिट्रोएन की बैसाल्ट

फ्रांस की वाहन निर्माता Citroen की ओर से जल्द ही नई एसयूवी को भारतीय बाजार में पेश किया जा सकता है। कंपनी की ओर से कब तक एसयूवी को पेश किया जा सकता है। इसमें किस तरह के फीचर्स दिए जा सकते हैं और कितना दमदार इंजन मिल सकता है। एसयूवी को किस कीमत पर लॉन्च किया जा सकता है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। फ्रांस की वाहन निर्माता Citroen जल्द ही भारतीय बाजार में नई SUV के तौर पर Basalt को पेश कर सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक Tata Curvv को चुनौती देने वाली इस कूपे SUV को कब तक और कितने दमदार इंजन के साथ लाया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं। सिट्रॉएन की ओर से बेसाल्ट कूपे एसयूवी को भारत में जल्द पेश किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी इस एसयूवी को August 2024 में पेश कर सकती है। जिसके बाद फेस्टिवल सीजन में इस एसयूवी को लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि अभी कंपनी की ओर से इस बारे में किसी भी तरह की आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। सिट्रॉएन बेसाल्ट कूपे एसयूवी को लॉन्च करने से पहले कंपनी की ओर से कई चरणों में टेस्टिंग की जा रही है। कुछ समय पहले ही टेस्टिंग के दौरान इसे देखा गया था। जिसमें अलॉय व्हील्स, प्रोजेक्टर हेडलाइट जैसे फीचर्स नहीं थे। टेस्टिंग के दौरान देखी गई यूनिट सामने से सी3 एयरक्रॉस की तरह दिखाई दे रही थी, जिसके साथ कूपे की तरह रूफलाइन भी दी गई थी।

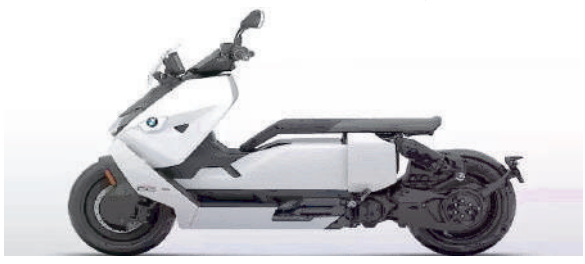

BMW CE 04 इलेक्ट्रिक स्कूटर प्री-बुकिंग हुई शुरू, इस दिन एंट्री मारेगा ये प्रीमियम ई-स्कूटर

BMW CE 04 भारत में किसी भी लग्जरी ब्रांड का पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर बन जाएगा। कंपनी इसे 24 जुलाई को ऑफिशियली लॉन्च करेगी और इसके लिए प्री-लॉन्च बुकिंग शुरू हो गई हैं। CE 04 इलेक्ट्रिक स्कूटर का डिजाइन मैक्सी-स्टाइल स्कूटर जैसा है और इसकी लंबाई दो मीटर से ज्यादा है। बेंच सीट और भारी फ्रंट फेस डिजाइन इसे सेगमेंट में प्रीमियम पेशकश के रूप में अलग बनाता है।

नईदिल्ली। जर्मन ऑटो दिग्गज BMW Motorrad भारत में अपना पहला प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। BMW की ओर से एक सप्ताह बाद इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमतें घोषित होने वाली हैं।

BMW CE 04 की बुकिंग डिटेल

BMW CE 04 भारत में किसी भी लग्जरी ब्रांड का पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर बन जाएगा। कंपनी इसे 24 जुलाई को ऑफिशियली लॉन्च करेगी और इसके लिए प्री-लॉन्च बुकिंग शुरू हो गई हैं। ये बुकिंग चुनिंदा अधिकृत BMW Motorrad डीलरशिप पर खुली हैं।

BMW CE 04 भारत में बिकने वाला सबसे महंगा इलेक्ट्रिक स्कूटर होने की उम्मीद है। यह ग्लोबल मार्केट में पहले से ही 11,795 डॉलर की कीमत पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। भारत में लॉन्च होने पर इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत लगभग 10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो सकती है। आइए, इसके बारे में जान लेते हैं।

डिजाइन और डायमेंशन

CE 04 इलेक्ट्रिक स्कूटर का डिजाइन मैक्सी-स्टाइल स्कूटर जैसा है और इसकी लंबाई दो मीटर से ज्यादा है। बेंच सीट और भारी फ्रंट फेस डिजाइन इसे सेगमेंट में प्रीमियम पेशकश के रूप में अलग बनाता है। CE 04 की लंबाई 2285 मिमी, चौड़ाई 855 मिमी, ऊंचाई 1,150 मिमी और सीट हाइट 780 मिमी है। इस ई-स्कूटर को 15 इंच के व्हील दिए गए हैं।

इंजन और परफॉर्मेंस

BMW CE 04 को लिक्विड-कूल्ड PMS इलेक्ट्रिक मोटर के साथ पेश किया जाएगा, जो लगभग 41 bhp की पावर और लगभग 60 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। ये 120 किमी प्रति घंटे तक की टॉप स्पीड पकड़ सकता है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से सीमित किया गया है।

ई-स्कूटर केवल 2.6 सेकंड में 0 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है। BMW CE 04 इलेक्ट्रिक स्कूटर को तीन राइडिंग मोड के साथ पेश करेगी जिसमें इको, रेन और रोड शामिल हैं।

बैटरी, चार्जिंग और रेंज

WMTC साइकिल के अनुसार, BMW CE 04 में 8.9 kWh बैटरी पैक होगा और एक बार चार्ज करने पर यह लगभग 130 किलोमीटर की रेंज देगा। बैटरी को लगभग 4 घंटे और 20 मिनट में 0-100 प्रतिशत तक रिचार्ज किया जा सकता है। साथ ही इसे डीसी फास्ट चार्जर का उपयोग करके 1 घंटा और 40 मिनट में फुल चार्ज किया जा सकता है।

स्पेसिफिकेशन

BMW CE 04 में ABS, ASC, इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स और ट्रैक्शन कंट्रोल शामिल होंगे। इसमें टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट, BMW Motorrad कनेक्टिविटी के साथ 10.25-इंच TFT डिस्प्ले, कीलेस राइड और वेंटिलेटेड स्टोरेज कम्पार्टमेंट भी दिया

ऑस्ट्रेलियाई बाज़ारों पर चीन का दबदबा, 80% से ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाहन यहीं बनेंगे

परिवहन विशेष न्यूज

बीजिंग (आईएएनएस) व (सौजन्य - चाइना मीडिया ग्रुप, बीजिंग)। ऑस्ट्रेलियाई चैंबर ऑफ ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज के मुख्य कार्यकारी टोनी वेबर ने हाल ही में कहा कि इस जून तक ऑस्ट्रेलियाई बाजार में बिकने वाले 80% से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन चीन में उत्पादित होते हैं। चीनी इलेक्ट्रिक वाहन ऑस्ट्रेलियाई बाजार में कम उत्सर्जन वाले वाहनों की मांग को पूरा करते हैं और उपभोक्ताओं की पसंद को समृद्ध करते हैं।

हाल के वर्षों में ऑस्ट्रेलियाई बाजार में प्रवेश करने वाली चीनी कारों की संख्या में वृद्धि जारी रही है, जो 2017 में लगभग 5,000 वाहनों से बढ़कर 2022 में लगभग 120,000 वाहन हो गई है। अब तक बीवाईडी ने ऑस्ट्रेलियाई बाजार में कई प्रकार के मॉडल लॉन्च किए हैं, जिनमें प्लग-इन हाइब्रिड यूटिलिटी वाहन शामिल हैं और इसमें दो एसयूवी और एक पिकअप ट्रक भी शामिल होंगे।

ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा ऊर्जा संरक्षण और उत्सर्जन में कमी की योजनाओं को बढ़ावा देना तथा व्यापार बाधाओं में कमी लाना, ऑस्ट्रेलिया में चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में वृद्धि के महत्वपूर्ण कारण हैं।

हाल के वर्षों में ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लगातार सहायक नीतियां पेश की हैं। मार्च 2023 में सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार, सर्वेक्षण में शामिल आधे से अधिक ऑस्ट्रेलियाई लोगों ने भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की इच्छा व्यक्त की।

केंद्रीय बजट में स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के उपाय अपेक्षित

परिवहन विशेष न्यूज

वित्त वर्ष 2024-25 के पूर्ण बजट से पहले सरकार अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों की घोषणा कर सकती है। विभिन्न उद्योगों से जुड़े लोगों ने इस बारे में पूर्वानुमान जताया है। आईसीआरए लिमिटेड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और समूह प्रमुख (कॉर्पोरेट रेटिंग) गिरीश कुमार कदम ने कहा कि बजट का मुख्य फोकस ग्रीन ग्रोथ पर आधारित रहने की उम्मीद है। उन्हें उम्मीद है कि बजट में अक्षय ऊर्जा, भंडारण, ट्रांसमिशन और वितरण नेटवर्क को मजबूत करने की योजनाओं पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। डेलॉइट में ऊर्जा, संसाधन और औद्योगिक क्षेत्र के उद्योग प्रमुख अश्विन जैकब ने कहा कि सरकार से सभी कार्बन क्रेडिट और नवीकरणीय ऊर्जा क्रेडिट (आरईसी) की बिक्री पर रियायती कर दरें प्रदान करने की भी उम्मीद है। यह केवल जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा मान्यता प्राप्त कार्बन क्रेडिट तक सीमित नहीं होना चाहिए। उन्होंने घरेलू मांग को बढ़ावा देने के लिए रिफाइनरियों और उर्वरकों जैसे क्षेत्रों के लिए हाइड्रोजन खरीद दायित्व (एचपीओ) की भी सिफारिश की।

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया के मानद सीईओ राजीव छाबा ने कहा है कि भारत में यात्री वाहनों पर मौजूदा जीएसटी दर संरचना काफी पुरानी हो चुकी है। इसे ऑटोमोटिव उद्योग में हो रहे बदलावों के अनुरूप बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार को ऑटोमोटिव क्षेत्र पर नीतियां बनाते समय वाहन उत्सर्जन, आयात बिल में कमी, टिकाऊ स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला और स्वामित्व की कुल लागत के समग्र परिप्रेक्ष्य पर विचार करना चाहिए।

हाइब्रिड कारों के बाद योगी सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर छूट 3 साल के लिए बढ़ाई

परिवहन विशेष न्यूज

उत्तर प्रदेश में हाइब्रिड वाहनों पर छूट देने के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर भी छूट बढ़ा दी है। अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दोपहिया वाहनों की खरीद पर 5,000 और चार पहिया वाहनों की खरीद पर 1,00,000 की सब्सिडी को अक्टूबर 2027 तक बढ़ा दिया है।

योगी आदित्यनाथ सरकार के प्रस्ताव को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी मंजूरी दे दी है। जारी अधिसूचना के अनुसार दोपहिया वाहनों के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसकी मदद से करीब 20 लाख वाहनों को सब्सिडी मिल सकेगी।

इसी प्रकार 25,000 वाहनों के लिए चार पहिया वाहनों पर 1,00,000 की छूट को मंजूरी दी गई है और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने चार पहिया वाहनों के लिए 250 करोड़ आवंटित किए हैं।

नियमों के मुताबिक यह छूट या सब्सिडी किसी भी इलेक्ट्रिक वाहन को खरीदने वाले ग्राहक को केवल एक बार ही दी जाएगी यानी कोई भी ग्राहक इलेक्ट्रिक वाहन पर सब्सिडी का लाभ केवल एक बार ही उठा सकेगा और दूसरी बार वाहन खरीदने पर कोई रियायत नहीं दी जाएगी।

समाचार एजेंसी आईएएनएस के मुताबिक राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति, 2022 में संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिसके अनुसार तिपहिया वाहनों पर मिलने वाली छूट को समाप्त कर दिया गया है। अभी तक सरकार तिपहिया वाहनों पर 12,000 की छूट देती थी और अब सरकार ने इसकी अवधि नहीं बढ़ाने का फैसला किया है।

प्रदूषण से मुक्ति और सुप्रीम कोर्ट

लक्ष्मीकांता चावला

जनता को यह कहा गया है कि नलबंदी-नसबंदी के बाद भी कुत्ते लोगों के आसपास ही छोड़े जाएंगे, पर यह नहीं बताया कि क्या ये कुत्ते बाद में भोंकना और काटना बंद कर देंगे। एक बार माननीय अदालत ने यह भी कहा था कि नींद लेना भी मानवीय अधिकार है। पुलिस जब किसी अपराधी को रात-रात भर सोने नहीं देती, उस घटना का संज्ञान लेते हुए देश की किसी बड़ी अदालत ने यह निर्णय दिया था, पर जो हमारे घरों के आसपास, गली बाजारों में रात रात भर कुत्ते चीखते हैं, वे भी तो हमें सोने नहीं देते। हमारा अधिकार कहां गया?

शोर का प्रदूषण, नींद न मिलना, गंदगी और कूड़े और इसके साथ ही शहर की सडक़ों पर चूहों का दौडऩा, घरों में अन्न दूषित करना, यह हमारे स्मार्ट शहरों का हाल है। अंतर इतना है कि घायल की गति घायल जाने और हमारे शासक, प्रशासक, यहां तक कि बड़े-बड़े कानूनविद भी आम घायल जनों की पीड़ा नहीं जानते। इसलिए मेरी एक विनम्र अपील जनहित में, देश के नब्बे प्रतिशत से भी ज्यादा जनता के हित में देश की न्यायपालिका से है कि हमें भी प्रदूषण मुक्त वातावरण दिलवाइए। हमें नींद का अधिकार मिलना ही चाहिए। हमें मच्छरों, मक्खियों, चूहों और कुत्तों के आतंक से बचाने का सरकारों को आदेश दीजिए'

यह सुखद, स्वस्थ समाचार है कि हाल ही में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है कि प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहना नागरिकों का मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली व आसपास ठोस कचरे का समुचित निस्तारण नहीं होने पर केवल नाराजगी ही नहीं, अपितु चिंता भी जताई है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि हम ठोस कचरे के शोधित न होने के कारण बहुत चिंतित हैं, क्योंकि प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का यह उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया क्या कहेगी, 2024 में भारत की राजधानी में प्रतिदिन 3800 टन ठोस कचरा अशोधित रह जा रहा है। 2025, 2026 और इसके बाद क्या होगा, हर जगह भयानक स्थिति है। गुरुग्राम, फरीदाबाद और ग्रेटर नोएडा जैसे क्षेत्रों में प्रतिदिन ठोस कचरा निकलने और उसे शोधित करने की क्षमता पर आंकड़ों का जिक्र करते हुए शीर्ष कोर्ट ने कहा कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में हो रहे विकास कार्यों पर विचार करें तो यह स्वाभाविक है कि इस कचरे में वृद्धि होगी, पर शहरी विकास सचिव को अधिकारियों के साथ बैठक कर समस्या का समाधान खोजने को कहा और यह भी चेतावनी दी कि अगर अधिकारी कोई ठोस प्रस्ताव खोजने में असमर्थ रहे तो अदालत कठोर आदेश जारी करने पर विचार करेगी।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हम देशवासियों की एक अपील है : बड़े-बड़े अधिवक्ताओं की मदद लेकर हम लोग अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकते, पर जब अदालत ने स्वयं ही यह अनुभव कर लिया कि प्रदूषण मुक्त वातावरण हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, तो देश के नब्बे प्रतिशत से ज्यादा नागरिक इस अधिकार से वंचित क्यों? क्या कभी किसी ने आकर देखा कि दिल्ली से दूर भी पूरे देश में कचरे का प्रकोप है। यह कचरा सब जगह ठोस तो नहीं है, पर कूड़े के बड़े-बड़े ढेर, गंदगी, बदबू, उस पर मक्खियों के झुंड, आसपास सीवरेज का गंदा पानी, यह हम लोगों की किस्मत है। जो स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए अपने देश में खर्च किए जा रहे हैं, स्मार्ट सिटी की घोषणा एक फैशन बन गया है, उसमें अपने देश के आम नागरिक कहीं स्थान नहीं पा रहे हैं क्या?

केवल सिविल लाइन क्षेत्र, अमीरों के मोहल्ले, उन्हीं का विकास हो रहा है। वैसे प्रदूषण तो शोर का भी होता है श्रीमान। उस शोर की अभी चर्चा नहीं की जा रही जो दिन रात मोटर गाडियां के हार्न से पैदा हो रहा है। हमारे तो गली मोहल्लों में भी रात-रात भर कुत्तों की चीख पुकार रहती है। एक नहीं अनेक आवारा कुत्ते हमारी सडक़ों पर लोगों का जीवन दूभर कर रहे हैं। लोग कटते हैं, कुछ मरते हैं, कुत्तों की गंदगी गली बाजारों में फैली रहती है, पर सरकार की योजना कि इनकी नलबंदी और नसबंदी करवाएंगे, तब शायद दस बीस वर्ष बाद संख्या कम होगी और उस समय तक जो लोग दुनिया में रहेंगे उन्हें कुत्तों से राहत मिलेगी, यह आम जनता के साथ क्रूर सरकारी मजाक है। सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश यह जानते होंगे कि सरकारें इन चौपायों के लिए प्यार तो प्रदर्शित करती हैं, पर जनता को इनके प्रहारों से बचाने का कोई प्रयास नहीं करती।

जनता को यह कहा गया है कि नलबंदी-नसबंदी के बाद भी कुत्ते लोगों के आसपास ही छोड़े जाएंगे, पर यह नहीं बताया कि क्या ये कुत्ते बाद में भोंकना और काटना बंद कर देंगे। एक बार माननीय अदालत ने यह भी कहा था कि नींद लेना भी मानवीय अधिकार है। पुलिस जब किसी अपराधी को रात-रात भर सोने नहीं देती, उस घटना का संज्ञान लेते हुए देश की किसी बड़ी अदालत ने यह निर्णय दिया था, पर जो हमारे घरों के आसपास, गली बाजारों में रात रात भर कुत्ते चीखते हैं, वे भी तो हमें सोने नहीं देते। हमारा अधिकार कहां गया?

इसके साथ ही भीड़ भरे मोहल्लों में शमशानघाट बने हैं। जो बड़े बड़े राजनेता स्वयं शहरों से दूर विशाल भवनों में, वृक्षों के झुरमुट में रहते हैं, वे राजनीतिक दबाव से इन शमशानघाटों को शहरों से दूर नहीं जाने देते, पर स्वयं जहां रहते हैं वहां शमशानघाट का धुआं पहुंचने की भी संभावना नहीं। अपने शहरों की घनी आबादियों में बने शमशानघाटों को शहर से दूर ले जाने के लिए लंबा संघर्ष करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती, क्योंकि राजनेता अधिक हावी-प्रभावी हो जाते हैं।

जिस युग में मानव चंद्रमा पर जाने की तैयारी में है, हर हाथ में मोबाइल और खानपान विदेशी ढंग का हो गया है, वहां पर ये सरकारें आज तक अंतिम संस्कार के लिए आधुनिक ढंग के विद्युत शवदाह गृह, आधुनिक पद्धति से अंतिम संस्कार जैसे साधन जनता को नहीं दे सकी। दिन-रात विदेश यात्राएं करने वाले ये नेता यूरोप-अमेरिका आदि देशों से यह नहीं देखकर आए कि वहां कैसे जनता अंतिम संस्कार के प्रदूषण से भी बची हुई है। सही बात यह है कि हमें पूरी पूरी रात लाउडस्पीकरों का शोर भी सहना पड़ता है। जिस कार्यक्रम में नेताजी आएंगे, वहां क्षेत्र के पुलिस अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी की सारी शक्तियां जवाब दे जाती हैं और वे लाउडस्पीकरों का शोर नियंत्रित नहीं कर पाते।

शोर का प्रदूषण, नींद न मिलना, गंदगी और कूड़े और इसके साथ ही शहर की सडक़ों पर चूहों का दौडऩा, घरों में अन्न दूषित करना, यह हमारे स्मार्ट शहरों का हाल है। अंतर इतना है कि घायल की गति घायल जाने और हमारे शासक, प्रशासक, यहां तक कि बड़े-बड़े कानूनविद भी आम घायल जनों की पीड़ा नहीं जानते।

इसलिए मेरी एक विनम्र अपील जनहित में देश के नब्बे प्रतिशत से भी ज्यादा जनता के हित में देश की न्यायपालिका से है कि हमें भी प्रदूषण मुक्त वातावरण दिलवाइए। हमें नींद का अधिकार मिलना ही चाहिए। हमें मच्छरों, मक्खियों, चूहों और कुत्तों के आतंक से बचाने का सरकारों को आदेश दीजिए। आम धार्मिक भाषा में कहते हैं- हारे को हरि नाम, पर मैं यह कह रही हूं कि जिनकी कोई नहीं सुनता, उनका न्यायालय संरक्षक-रक्षक बने, तभी आम जन सुविधा से जी सकता है, खा सकता है, सो सकता है और शुद्ध वायु में श्वास ले सकता है।

इसी के साथ प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नागरिक समाज को भी आगे आना होगा। सामाजिक संगठनों को बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाना होगा। स्कूलों, कालेजों और विश्वविद्यालयों में छात्रों को जागरूक किया जाना चाहिए, ताकि वे घर-घर जाकर गांवों-शहरों के लोगों को प्रदूषण न फैलाने की सीख दे सकें। प्रदूषण से निपटने के लिए पूरे देश में संयुक्त प्रयासों की जरूरत है। इससे निपटना केवल सरकार का दायित्व नहीं है। सरकार पर निर्भर रहकर हम परिणाम देख चुके हैं। अतः नागरिक समाज का आगे आना नितांत आवश्यक है। जो अधिकारी जनता को प्रदूषण मुक्त वातावरण उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं, उन पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए।

संपादकीय

रोजगार या नौकरी

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीते 3-4 साल में करीब आठ करोड़ रोजगार दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने भारतीय रिजर्व बैंक की एक रपट का हवाला दिया है। प्रधानमंत्री के मुताबिक, बुनियादी ढांचे की प्रत्येक परियोजना के साथ-साथ रोजगार भी बढ़ता है। इस मुद्दे पर फर्जी आंकड़े और बयान देने वालों की जुबान अब बंद हो जानी चाहिए, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े अब भी प्रधानमंत्री के दावे को 'झूठ' करार दे रहे हैं। वह रोजगार के मुद्दे को मोड़ कर पेपरलीक, एनटीए और एनटीआर पर ले आए हैं और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने सरीखे सवाल पूछ रहे हैं। उनकी अपनी कुंठाएं हैं। बेशक रोजगार और महंगाई इस दौर के सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे हैं। आम चुनाव भी बेरोजगारी से प्रभावित हुआ है, ये विश्लेषण अब सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के बयान के संदर्भ में भी सवाल यह है कि ये रोजगार क्या हैं? नौकरी, दिहाड़ी, स्वरोजगार, ठेका अथवा मनरेगा किस्म का रोजगार है! यदि नौकरियां दी गई हैं, तो वे निजी क्षेत्र में भी कितनी स्थायी हैं? निजी क्षेत्र देश के निर्माण और विकास में बराबर का भागीदार है। विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बनने में निजी क्षेत्र का ज्यादा योगदान है। सरकारी क्षेत्र की परिधियां सीमित होती हैं। यदि आज भी करीब 10 लाख सरकारी नौकरियां रिक्त पड़ी हैं, तो यह सरकार की नीयत और इच्छा का ही नतीजा है। सरकारें अपने क्षेत्र को सिकोड़ देना चाहती हैं और सरकारी काम को आउटसोर्स के हवाले कर रही हैं। बहरहाल प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्रसिंह ने बीते दिनों एक बयान दिया था कि भाजपा-एनडीए सरकार ने 2014-23 के दौरान 9 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं। यह आंकड़ा यूपीए सरकार के 2004-13 कार्यकाल से बेहतर है, क्योंकि उस सरकार के दौरान 6 लाख सरकारी नौकरियां ही दी गई थीं। ये आंकड़े भी 'ऊंट के मुंह में जीरा' समान हैं। भारतीय स्टेट बैंक के मुताबिक, 2014-23 के दौरान 12.5 करोड़ रोजगार दिए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री रिजर्व बैंक के जरिए यह भी स्पष्ट करें कि किन क्षेत्रों में रोजगार दिए गए हैं और वे कितने स्थिर हैं?

भारत की कुल आबादी करीब 143 करोड़ है, लेकिन 2024 तक कुल कार्यबल 64.33 करोड़ है। यह आंकड़ा 2023 में 59.67 करोड़ था। एक साल में 4.67 करोड़ कार्यबल की बढ़ोतरी हुई है। इतने हाथों में नौकरी, रोजगार या दिहाड़ी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री यह भी स्पष्ट करें कि यह देश का सालाना औसत रोजगार है अथवा 2023-24 के ही आंकड़े हैं? यदि ऐसा होता, तो जून में देश की बेरोजगारी दर करीब 9 फीसदी न होती। ऐसा भी न होता कि नौकरी के लिए 10 स्थान खाली हैं और उनके लिए सैकड़ों की भीड़ उमड़ आती है और कंपनी की बाहर की रेलिंग भी टूट जाती है। सरकारी प्रवक्ताओं की ओर से भी यह दावा किया जाता रहा है कि 2017-मार्च 2024 के दौरान 6.2 करोड़ नौकरीपेशा 'कर्मचारी भविष्य निधि संगठन' (ईपीएफओ) से जुड़े हैं। जाहिर है कि इतने लोगों को सरकारी, अद्र्धसरकारी और निजी क्षेत्र में नौकरियां मिली होंगी! ईपीएफओ की निरंतरता पर भी सवाल किए जाते रहे हैं। 2021 से अब तक करीब 7.8 करोड़ रोजगार का सृजन किया जा चुका है। रोजगार के आंकड़े तैयार करने में भी भ्रष्टाचार किया जाता है। मसलन-कृषि में करीब 6 करोड़ रोजगार ऐसे हैं, जहां महिला अपने पति का हाथ बंटाने खेत पर जाती है। उसे 'स्वतंत्र रोजगार' नहीं मान सकते, क्योंकि उसका कुछ भी मानदेय या वेतन अथवा दिहाड़ी तय नहीं है। बेशक भारत में निजी क्षेत्र का बहुत विस्तार हुआ है। विदेशी कंपनियां आई हैं और उन्होंने उत्पादन के प्लांट स्थापित किए हैं। जाहिर है कि उनमें भारतीय ही प्राथमिकता के स्तर पर काम कर रहे हैं। देश में करीब 3 लाख स्टार्टअप कार्यरत हैं। उनमें भी रोजगार के अवसर हैं। प्रधानमंत्री ने इस पद पर आने से पहले देश की जनता से वायदा किया था कि यदि उनकी सरकार आई, तो 2 करोड़ रोजगार हर साल पैदा करेंगे। उस वायदे में 'रोजगार' के मायने नौकरी भी होंगे। बेशक इतने व्यापक देश में प्रत्येक पात्र नागरिक को सरकारी नौकरी मुहैया नहीं कराई जा सकती, लेकिन निजी क्षेत्र में नौकरी भी उतनी ही मूल्यवान और महत्वपूर्ण है।

राय

बदलते पैमाने

लोकसभा के चरित्र में राजनीतिक पहुंच के पैमाने, कांग्रेस की धुरी बदल रहे हैं, तो राष्ट्रीय बहस के करीब पार्टी का आत्मविश्वास-आत्मबल बढ़ा है। इसी परिप्रेक्ष्य में हिमाचल में सत्ता का हासिल कांग्रेस को फिर से मजबूत पायदान पर पहुंचा देता है, फिर भी लोकसभा और विधानसभा के चुनावों के आईने अलग-अलग रहे हैं। पूरी चार सीटों पर लोकसभा के रास्ते भाजपा के लिए खुले, लेकिन कांग्रेस की दौड़ राज्य से बाहर नहीं पहुंची। अब जिक्र उन पैमानों का जिनके कारण ठेस लगी और पार्टी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने खोज लिए गुनाह, अपने बंजर हुए चरागाह। मूलतः प्रश्न अगर व्यक्तित्व का है तो कांग्रेस को ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि दुनिया लट्टू बनकर मोदी के इर्द-गिर्द घूम रही है और यह भी कि राम मंदिर ने वोट हथिया लिए। अगर व्यक्तित्व की ताल पर मोदी आगे हैं, तो प्रदेश सरकार की ढाल पर मुख्यमंत्री के पद पर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की कांग्रेस और आलाकमान का पूर्ण विश्वास भी तो है। यानी जनता अगर सुक्खू सरकार को अस्थिर होने से बचा रही है, तो राजतिलक में शिमला की सत्ता ने लोकसभा चुनाव की आजमाइश में उतनी गंभीरता नहीं दिखाई जितनी छह जमा तीन उपचुनावों में ताकत सामने आई। यह आत्मविश्वास था और जीतने का मॉडल भी जो लोकसभा में भाजपा की जीत से चार उपचुनाव छीन लाई। अनुराग को दिल्ली का टिकट देने वाली जनता शिमला के पक्ष में सुक्खू सरकार का ओहदा चिन्हित करती है, तो यह एकतरफा मोदी प्यार नहीं हो सकता, बल्कि जनता अपनी अपेक्षाओं के फलक पर दिल्ली और शिमला के बीच राजनीतिक अर्थ को बांट रही थी। जहां तक अयोध्या मंदिर निर्माण की दुहाई दी जा रही है, तो वर्षों पहले बाबरी विध्वंस के उफान पर शांता कुमार सरकार को समय पूर्व गिराने के बावजूद इसी जनता ने उसकी वापसी रोकी थी, यानी हिमाचल में हिंदुत्व का मुद्दा या धार्मिक उन्माद की पहचान से वोट बैंक नहीं बनता। इसे प्रमाणित करते हैं हिमाचल से अयोध्या बस सेवाओं के रूट, जहां रूट पर बची एकमात्र सेवा साप्ताहिक करने के बावजूद यात्री नहीं ढूंढ पा रही है। यह दीगर है कि किसान निधि की किस्त चमत्कारी हो सकती है, लेकिन अपनी दस गारंटियों में से पांच पर अमल करने का दावा करके हिमाचल की सत्ता के प्रति आकर्षण कम नहीं होता। यहां भी औरतों को पंद्रह सौ की पेशकश तथा ओल्ड पेंशन स्कीम का लागू होना सत्ता के पक्षधर वर्ग की शिनाख्त करता है। कांग्रेस के दो कारण पार्टी और सरकार की क्षमता दर्शा रहे हैं। सरकार बनाम संगठन के बीच दूरियां एक स्थापित तथ्य है, जहां शक्तियों का आबंटन असंतुलित, अव्यवहारिक और असंगत रहा है, वरना छह अपने और तीन निर्दलीय रुखसत न होते। जिस सरकार को मात्र सवा साल में अपने नौ समर्थक विधायकों से सीधे चुनाव में भिडऩा पड़ा हो, वहां आज की हार-जीत कल के खतरे बढ़ाती है। उपचुनाव केवल एक परिणाम नहीं, आने वाले कल की तासीर, घुटन और तस्वीर लिए हुए हैं। यहां सत्ता बल या संख्या की मात्रात्मक आपूर्ति के बावजूद सरकार और संगठन के बीच हाथों में मसले बराबर बंटने चाहिए। कुछ इसी तरह का उल्लेख अफसरशाही के बेलगाम इरादों पर उठे हैं। यह प्रशासनिक क्षमता का निठल्लापन हो सकता है, लेकिन इससे भी कहीं अधिक ठोस इरादों, सरकार की जिम्मेदारी-जवाबदेही व पारदर्शिता का हाल है। अगर अफसरशाही से कांग्रेस के नेता ही उदास हैं, तो आम आदमी को न्याय कहां मिलेगा। दरअसल जहां सरकार को होना चाहिए, वहां संगठन में सत्ता बंट गई और जहां सत्ता को होना चाहिए, वहां संगठन की कमियां सरकार विरोधी हो गईं। बेहतर होगा कांग्रेस यह सोचे कि कुल नौ विधायक एक ही समय में सरकार के खिलाफ क्यों हुए और क्या अब चुनावों के बाद पार्टी की सत्ता में तहजीब बदल गई।

जान-माल की क्षति रोकने को चाहिए ठोस नीति

इन सीमेंट प्रोजेक्ट्स के स्थान पर प्रदेश में बागबानी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि हमारा प्रदेश संसार भर में फल तथा जड़ी-बूटियों पर आधारित प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध हो सके और यहां का पर्यावरण भी हरे-भरे पेड़ों की वजह से साफ-सुथरा तथा प्रदूषणमुक्त बना रहे'

हिमाचल प्रदेश, जिसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, में साल 2023 में जून महीने से लेकर अक्तूबर महीने तक सदी की अभूतपूर्व बरसात हुई थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार सारे प्रदेश में लगभग 503 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी तथा 519 आदमी घायल हुए थे। इनमें 199 आदमियों की सडक़ हादसों में मौत हुई थी। प्रदेश में 2941 घर पूरी तरह ढह गए थे तथा 12302 को आंशिक नुकसान पहुंचा था। इसके अतिरिक्त 421 दुकानों तथा 7247 गौशालाओं को भी नुकसान हुआ था। उस समय प्रदेश में भूस्खलन की 169 और अचानक बाढ़ की 72 बड़ी घटनाएं सामने आई थी। प्रदेश में भूस्खलन यानी छोटे-छोटे डंगे गिरने की हजारों घटनाएं घटित हुई थीं। पिछले साल इन प्राकृतिक आपदाओं से प्रदेश सरकार को आर्थिक तौर पर लगभग 9712 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। फिर भी भगवान की कृपा से प्रदेश के वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री और उनकी सरकार ने इस प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए काफी कुछ उपाय किए, जो सराहनीय हैं। इस बार मानसून आ चुका है, भले ही उतनी बारिश नहीं हो रही, जितनी अपेक्षा है। आने वाले समय में बहुत बारिश हो सकती है, जिसके लिए निकट भविष्य में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान के बचाव के लिए जरूरी सुझाव लेखक की तरफ से प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री महोदय को एक पत्र के रूप में तिथि 03-05-2024 को भेजे गए हैं, जिनमें से कुछ मुख्य सुझाव यहां दिए जा रहे हैं : प्रदेश में जितने भी 80-100 साल से ज्यादा के पुराने रिहायशी मकान, दुकानें या गौशालाएं हैं, उनको राजस्व विभाग की तरफ से असुरक्षित भवन घोषित किया जाए।

इस कार्य को करने के लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, पीडब्ल्यूडी तथा दूसरे विभागों की मदद ली जा सकती है। इन असुरक्षित भवनों को गिराने का कार्य बरसात से पहले-पहले करवाया जाए ताकि इन पुराने भवनों के अचानक गिरने से पहले जान-माल की रक्षा हो सके और प्रदेश सरकार को मुफ्त में इन मकान मालिकों को लाखों-करोड़ों रुपयों का हर्जाना भी न देना पड़े। प्रदेश में जितनी भी सडक़ें हैं, उनके किनारे पानी की निकासी की नालियों को जल्दी से जल्दी पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों से साफ करवाया जाए। इसके साथ जो ल्हासे अभी भी सडक़ों पर गिरे हुए हैं या छोटे-छोटे डंगे पिछली बरसात के दौरान गिरे हुए हैं, उनका निर्माण कार्य अति शीघ्र करवाया जाए ताकि आने वाले समय में भूस्खलन की घटनाएं और जान-माल का नुकसान भी कम से कम हो सके। हमारे इस पहाड़ी प्रदेश में कई बार बरसात के दिनों में कहीं-कहीं रिहायशी मकानों तथा गौशालाओं के ऊपर बड़े-बड़े पेड़ जड़ों से उखड़ कर गिर जाते हैं जिसके कारण कई बार जान-माल का भी नुकसान हो जाता है और प्रदेश सरकार को इन घटनाओं से पीड़ित लोगों के लिए आर्थिक सहायता भी देनी पड़ती है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रदेश सरकार को सख्त कानून बनाना चाहिए तथा ग्राम पंचायतों, नगर परिषदों, नगर निगमों और वन विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों को मौके पर जाकर इन खतरनाक पेड़ों को काटने के आदेश तत्काल दिए जाने चाहिए ताकि निकट भविष्य में ऐसी घटनाएं कम से कम हों। प्रदेश में जितने भी छोटे-छोटे चो-नाले हैं या छोटी-छोटी खड्डें हैं, उनके बीच में जो छोटी-छोटी झाडियां उगी हुई हैं या जो लोकल लोगों ने कूड़ा-करकट फैंका हुआ है, इनकी सफाई अति शीघ्र करवाई जाए ताकि वर्षा ऋतु में इन चो-नालों तथा खड्डों का बहाव ठीक बना रहे और बाढ़ की स्थिति पैदा न हो। पहाड़ी प्रदेश होने के नाते यहां की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए इस प्रदेश में आगे से नई जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण बंद करवाया जाए ताकि खड्डों-नालों में बाढ़ का प्रकोप कम हो सके और पर्यावरण भी ठीक से बना रहे। इसकी बजाय माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार द्वारा सौर ऊर्जा से बनाई जाने वाली मुफ्त की बिजली उत्पादन संबंधी स्कीमों को निकट भविष्य में बढ़ावा दिया जाए। इस प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए 4-लेन वाली सडक़ों के निर्माण पर भविष्य में पाबंदी लगाई जाए, सिर्फ यहां पर 2-लेन वाली सडक़ें ही बनाई जाएं ताकि आने वाले समय में इस प्रदेश में बढ़ते भूस्खलन को रोका जा सके। जहां तक हो सके, सडक़ों के किनारे ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाएं ताकि इस पहाड़ी प्रदेश का जलवायु भी स्वच्छ बना रहे। इस पहाड़ी प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए और साल 2023 की अभूतपूर्व आपदा के अनुभव से प्रदेश सरकार को भवन निर्माण की मंजूरी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) की हिदायतों के अनुसार देनी चाहिए। सारे प्रदेश को टीसीपी के दायरे में लाया जाए ताकि इस प्रदेश में अंधाधुंध बड़े-बड़े ऊंचे बेतरतीब भवनों के निर्माण पर नियंत्रण किया जा सके और आने वाले समय में और ज्यादा होने वाली प्राकृतिक आपदाओं से इस देवभूमि को अनिवार्य रूप से बचाया जा सके।

इस पहाड़ी प्रदेश में आगे से और कोई सीमेंट बनाने के नए प्रोजेक्ट न लगाए जाएं क्योंकि इससे एक तो हमारे पहाड़ खोखले हो रहे हैं जिससे पर्यावरण को बड़ा-भारी खतरा बना हुआ है, तथा साथ ही इनसे प्रदेश के लोगों को सांस-दमे की बीमारी बढ़ रही है। इन सीमेंट प्रोजेक्ट्स के स्थान पर प्रदेश में बागबानी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि हमारा प्रदेश संसार भर में फल तथा जड़ी-बूटियों पर आधारित प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध हो सके और यहां का पर्यावरण भी हरे-भरे पेड़ों की वजह से साफ-सुथरा तथा प्रदूषण मुफ्त बना रहे। अतः प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि इन सुझावों पर अति शीघ्र कार्रवाई करवाने के लिए प्रदेश के सारे जिला उपायुक्तों को निर्देश जारी किए जाएं ताकि आने वाली बरसात में प्राकृतिक आपदाओं से इस पहाड़ी प्रदेश में जान-माल का नुकसान कम से कम हो और प्रदेश सरकार का भी करोड़ों रुपयों का आर्थिक नुकसान होने से बच सके। इसके अलावा मैं प्रदेश के नवनिर्वाचित सांसदों से अपील करना चाहूंगा कि वे प्रदेश को केंद्र से राहत पैकेज दिलवाएं ताकि पिछली साल बरसात से जो जख्म मिले, उन पर मरहम लगाया जा सके।

रणजीत राणा

लो जी, बरसात आ गई

लो जी! बरसात आ गई! अब बरसात में साल भर पेड़ काटने वाले कंधों पर कुदाल हाथ में मोबाइल ले जहां भी जगह मिलेगी वहीं पौधे लगाने निकल पड़ेंगे। वे पौधा एक लगाएंगे तो उसके साथ सेल्फी दस खिचवाएंगे। लो जी! बरसात आ गई! जिन सरकारी ठेकेदारों द्वारा कराए सरकारी निर्माणों की पेमेंट उनको हो चुकी है, वे आसमान में बादलों के न गरजने के बाद भी मोर बन नाचने लगेंगे। जिन सरकारी ठेकेदारों को उनके द्वारा कराए निर्माणों की पेमेंट अभी अटकी है वे बरसात से दोनों हाथ जोड़ प्रार्थना करेंगे कि हे बरसात! जब तक उनके द्वारा कराए सी ग्रेड सरकारी कामों की सरकार से पेमेंट नहीं हो जाती तब तक बरसना मत प्लीज! सच कहें तो इस निर्माण में हमें कुछ भी नहीं बचा है। ऊपर से नीचे तक इतना चढ़ावा चढ़ाना पड़ा है कि कुछ खाने के बदले उलटा अपनी जेब से लगाया है ताकि उन्हें लगे कि वे सरकार के विकासात्मक हाथों के साथ अपना हाथ मिला देश को गिरा रहे हैं। ऐसे में जो उनके द्वारा बनाया पुल पेमेंट होने से पहले ही जरा सी भी बरसात होने पर ढह बह गया तो उनके पेट पर लात पड़ जाएगी। लो जी! बरसात आ गई! बरसात आने की शुभ सूचना मौसम विभाग से पहले मेरा पड़ोसी देता है। उसे मौसम विभाग से पहले ही पता नहीं कहां से पता चल जाता है कि अब बरसात आने वाली है। जैसे ही उसे उसके विश्वस्त सूत्रों से बरसात आने की पुख्ता सूचना मिलती है, वह अपने घर का सारा पानी मेरे घर की ओर मोड़ देता है। जब वह अपने घर का पानी मेरे घर की ओर मोडने लगे तो मैं भी अनुमान लगा लेता हूं कि अब पक्का बरसात आने वाली है। मौसम विभाग को पता हो या न! लो जी! बरसात आ गई! बरसात आते ही मेरे स्वच्छ शहर का सारा कूड़ा कचरा सडक़ों पर पर्यटकों की तरह घूमने निकल पड़ेगा। बरसात आते ही चार महीने से बरसात से निपटने की सरकार की तमाम तैयारियों पर झाड़ू फिर जाएगा। शहर पानी पानी हो जाएगा।

तब कोई कागज की कश्ती में ऑफिस जाएगा तो कोई तो कोई बचाव के लिए कागज की कश्ती! कश्ती चिल्लाएगा। लो जी! बरसात आ गई! बरसात के आते ही सारे टीवी चैनलों के बरसाती रिपोर्टर बरसाती पहने नदी नालों के किनारे जम जाएंगे और नदी नालों से नदी नालों को लाइव कवर कर बरसाती चैनलों में सबसे तेज हो जाएंगे। लो जी! बरसात आ गई! अब बारिश किसान से आंख मिचौली खेलेगी। किसान से सभी आंख मिचौली खेलते हैं। कभी उससे दलाल आंख मिचौली खेलता है तो कभी सरकार उससे आंख मिचौली खेलती है। उसे दुख इस बात का है कि वह किसी से भी आंख मिचौली नहीं खेल पाता। लो जी! बरसात आ गई! अब किसान कभी सूखे से फसल को उदास हो बादलों की ओर टकटकी लगाए देखेगा तो कभी बाढ़ में डूबी फसल को देख दिल्ली से हवाई जहाज में आने वालों की ओर देखेगा। लो जी! बरसात आ गई! अब मौसम विभाग जिस दिन कहेगा कि आज मौसम साफ रहेगा उस दिन बरसात झमाझम बरसेगी। मौसम विभाग जिस दिन बारिश का रेड अलर्ट जारी करेगा उस दिन मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। जिस दिन मौसम विभाग कहेगा कि आज भारी से भारी बारिश होगी तो सरकार स्कूलों में अवकाश कर देगी। पर उस दिन सूरज चमाचम चमकेगा।

मौसम विभाग और बरसात की आपस में पता नहीं क्यों सैंतीस का आंकड़ा है। लो जी! बरसात आ गई! संसद में मानसून सत्र शुरू होते ही सब एक दूसरे पर बरसात की तरह बरसेंगे, बादलों की तरह गरजेंगे। नदी नालों की तरह शोर मचाएंगे। मेंढकों की तरह टर्राएंगे। पर जनता के मतलब के बिल पूरी तरह बरसात न होने के बाद भी बरसात में सिर से पांव तक भीग जाएंगे। उन बिलों को सर्दी हो जाएगी, खांसी हो जाएगी, जुकाम हो जाएगा। डेंगू हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा। तब आम आदमी बरसात में भीगता हुआ सर्दी की सैंपल फेल दवा खाएगा, जुकाम की सैंपल फेल दवा खाएगा, डेंगू की सैंपल फेल दवा खाएगा, खांसी की सैंपल फेल दवा खाएगा, मलेरिया की सैंपल फेल दवा खाएगा। और खुशी की बात! सैंपल फेल दवाइयों का सेवन कर वह फिर अगले मौसम में बीमार होने के लिए ठीक हो जाएगा। लो जी! बरसात आ गई! लो जी! बरसात आ गई!

अशोक गौतम
ashokgautam001@gmail.com

इन कंपनियों के शेयर ने किया निवेशकों को मालामाल, 1 साल में हुआ तगड़ा मुनाफा

स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार एलआईसी का शेयर 18 जून 2023 को 620 रुपये से लगभग 79 प्रतिशत बढ़कर मंगलवार को बंद होने पर 1109 .15 रुपये पर पहुंच गया। वहीं एचडीएफसी लाइफ ने समान अवधि में नकारात्मक रिटर्न दिया। यह मंगलवार को बीएसई पर 646 .55 रुपये के बंद भाव था। वहीं एक साल पहले एचडीएफसी का शेयर 666 .55 रुपये पर था।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की दिग्गज कंपनी जीवन बीमा निगम (LIC) के शेयरों ने एचडीएफसी लाइफ और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ जैसी प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, एलआईसी का शेयर 18 जून 2023 को 620 रुपये से लगभग 79 प्रतिशत बढ़कर मंगलवार को बंद होने पर 1,109.15 रुपये पर पहुंच गया। वहीं, एचडीएफसी लाइफ ने समान अवधि में नकारात्मक रिटर्न दिया। यह मंगलवार को बीएसई पर 646.55 रुपये के बंद भाव था। वहीं, एक साल पहले एचडीएफसी का शेयर 666.55 रुपये पर था।

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने 12 प्रतिशत का रिटर्न दिया। इसके शेयर की कीमत 18 जून 2023 को 582 रुपये से बढ़कर 16 जून 2024 को 654.10 रुपये हो गई।

एसबीआई लाइफ़ इंश्योरेंस से मिला 23% रिटर्न

पिछले एक साल में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के शेयर 1,314 रुपये से बढ़कर 1,621.20 रुपये पर पहुंच गए हैं, जिससे 23 फीसदी का रिटर्न मिला है। वॉरेन बफेट के स्वामित्व वाली बर्कशायर हैथवे सहित (Berkshire Hathaway) प्रमुख वैश्विक कम्पनियां अपनी बेहतर निवेश क्षमता के कारण सफल रही हैं।

विश्लेषकों का कहना है कि अधिकांश भारतीय बीमा कम्पनियां अभी तक देश के बुनियादी ढांचा क्षेत्र के उभरने का लाभ नहीं उठा पाई हैं।

बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में अधिक निवेश के साथ एसबीआई के शेयर में इस साल 48 प्रतिशत की वृद्धि हुई है (मंगलवार को 592 रुपये से 880.95 रुपये तक), जबकि एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक के शेयरों में केवल (-)3 प्रतिशत से 24 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर 18 जून 2023 को 1,895 रुपये पर थे और मंगलवार को 1,805.20 रुपये पर बंद हुए। एचडीएफसी बैंक मंगलवार को बीएसई पर 1,619.20 रुपये पर बंद हुआ, जो एक साल पहले 1,679 रुपये था।

भारतीय बीमा कंपनियों ने इन क्षेत्रों में किया निवेश

भारतीय बीमा कंपनियों ने बीएफएसआई, आईटी और उपभोक्ता क्षेत्रों में निवेश केंद्रित किया है - ये सभी हाल के दिनों में कम प्रदर्शन करने वाले रहे हैं। उनका केवल 8-10 प्रतिशत निवेश बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में है। वैश्विक मानकों की तुलना में यह बहुत कम है।

विश्लेषकों ने बताया कि बड़ी वैश्विक बीमा कम्पनियां - जैसे एलियांज, निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस और मेटलाइफ, तथा अन्य बीमा कम्पनियां जैसे बर्कशायर हैथवे - का बुनियादी ढांचा क्षेत्र में 15 से 30 प्रतिशत तक का निवेश है।

भारत के लिए, इस क्षेत्र पर सरकार के मजबूत फोकस के साथ बड़े पैमाने पर खर्च, पहल का समर्थन, नीतियों को प्रोत्साहित करना और शासन में सुधार, बुनियादी ढांचा उद्योग ने अपनी क्षमता से आगे निकल गया है। विश्लेषकों के अनुसार, इससे बुनियादी ढांचा क्षेत्र को अन्य सभी क्षेत्रों से बेहतर प्रदर्शन करने में मदद मिली है।

इस साल अब तक 30 प्रतिशत चढ़ा BSE मिडकैप इंडेक्स, स्मालकैप में भी आया उछाल

विश्वास और तरलता में सुधार के बीच छोटी कंपनियों ने बड़ी कंपनियों से आगे निकलकर निवेशकों को बेहतर रिटर्न दिया है। जहां बीएसई मिडकैप सूचकांक 29 .81% बढ़कर 10984 .72 अंक पर पहुंच गया। वहीं स्मालकैप 27 .24% बढ़कर 11628 .13 अंक पर पहुंच गया। यह दर्शाता है कि घरेलू निवेशकों का भरोसा लौट रहा है और वे जोखिम लेने के लिए तैयार हैं।

नई दिल्ली। देश की वृहद आर्थिक बुनियाद को लेकर भरोसे तथा घरेलू स्तर पर तरलता की स्थिति में सुधार के बीच इस साल अब तक छोटी कंपनियों के शेयरों ने निवेशकों को अधिक रिटर्न दिया है। बीएसई मिडकैप सूचकांक इस वर्ष 16 जुलाई तक 10,984.72 अंक या 29.81 प्रतिशत चढ़ा है, जबकि स्मालकैप में 11,628.13 अंक या 27.24 प्रतिशत का उछाल दर्ज किया गया है।

स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक सुनील न्याति ने कहा कि मिडकैप और स्मालकैप शेयरों के बेहतर प्रदर्शन की मुख्य वजह घरेलू स्तर पर नकदी में उछाल है। म्यूचुअल फंड, पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं (पीएमएस) और प्रत्यक्ष निवेश के जरिये इन क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में घरेलू धन का प्रवाह हो रहा है।

क्यों पीछे रहें शेयर

उन्होंने कहा कि हम वर्तमान में एक संरचनात्मक तेजी वाले बाजार में हैं, जहां मिडकैप और स्मालकैप शेयर बेहतर प्रदर्शन करते हैं। हालांकि बड़े शेयरों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की बिकवाली के कारण वे मिडकैप और स्मालकैप शेयरों से पीछे रह गए।

बीएसई मिडकैप सूचकांक इस साल 16 जुलाई को 48,175.21 अंक के अपने सर्वकालिक उच्चस्तर पर पहुंच गया, जबकि स्मालकैप आठ जुलाई को 54,617.75 अंक के अपने सर्वकालिक उच्चस्तर पर पहुंचा था। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 16 जुलाई को 80,898.3 अंक के अपने रिकार्ड उच्चस्तर पर पहुंचा था।

क्यों बेहतर रहा मिडकैप तथा स्मालकैप का प्रदर्शन

मास्टर कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, अरविंदर सिंह नंदा ने कहा कि इस वर्ष सेंसेक्स की तुलना में मिडकैप तथा स्मालकैप सूचकांक के बेहतर प्रदर्शन की वजह प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा और उपभोक्ता वस्तुओं में क्षेत्र-विशेष में उछाल और उनका निचला मूल्यांकन तथा अर्थव्यवस्था की उच्च वृद्धि क्षमता को दिया जा सकता है।

एडीबी ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 7% पर रखा बरकरार

एशियाई विकास बैंक (ADB) ने बुधवार को चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के अनुमान को 7 प्रतिशत पर बरकरार रखा। एडीबी का यह पूर्वानुमान अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा भारत के लिए अपने जीडीपी विकास अनुमानों को अप्रैल में अनुमानित 6 .8 प्रतिशत की तुलना में 7 प्रतिशत तक संशोधित करने के बाद आया है।

नई दिल्ली। एशियाई विकास बैंक (ADB) ने बुधवार को चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के अनुमान को 7 प्रतिशत पर बरकरार रखा। सामान्य से अधिक मानसून अनुमानों को देखते हुए कृषि में सुधार की उम्मीद है। एडीबी का यह पूर्वानुमान अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा भारत के लिए अपने जीडीपी विकास अनुमानों को अप्रैल में अनुमानित 6.8 प्रतिशत की तुलना में 7 प्रतिशत तक संशोधित करने के बाद आया है।

पिछले महीने, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपने विकास पूर्वानुमान को संशोधित कर 7.2 प्रतिशत कर दिया, जो पहले अनुमानित 7 प्रतिशत था। एशियाई विकास आउटलुक (ADO) के जुलाई संस्करण में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2024 (31 मार्च 2025 को समाप्त) में 7 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2025 (अगले वित्तीय वर्ष) में 7.2 प्रतिशत की दर से बढ़ने की राह पर है, जैसा कि ADO अप्रैल 2024 में अनुमान लगाया गया है।

पिछेल वित्त वर्ष के मुकाबले इस बार बढ़ी जीडीपी ग्रोथ रेट

वित्त वर्ष मार्च 2024 तक के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था ने 8.2 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह 7 प्रतिशत थी।

वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में सेवाओं का विस्तार मज़बूती से जारी रहा और भविष्य की ओर देखने वाली सेवाओं का PMI अपने दीर्घकालिक औसत से काफ़ी ऊपर है। ADB ने उद्योग में भी मज़बूती से वृद्धि होने की उम्मीद जताई है, जो विनिर्माण और आवास के नेतृत्व में निर्माण की मज़बूत मांग से प्रेरित है।

मानसून अनुमानों के साथ कृषि में उछाल की उम्मीद

रवित्त वर्ष 2023 में धीमी वृद्धि के बाद, सामान्य से ऊपर के मानसून अनुमानों को देखते हुए कृषि में फिर से उछाल आने की उम्मीद है। यह जून में मानसून की धीमी प्रगति के बावजूद है। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गति को बनाए रखने के लिए कृषि में फिर से उछाल आना महत्वपूर्ण होगा।

सार्वजनिक निवेश ने निवेश की मांग हुई मजबूत

इसमें कहा गया है कि सार्वजनिक निवेश के कारण निवेश की मांग मजबूत बनी हुई है और बैंक ऋण से आवास की मजबूत मांग को बढ़ावा मिल रहा है तथा निजी निवेश की मांग में सुधार हो रहा है। हालांकि, इसमें कहा गया है कि निर्यात वृद्धि सेवाओं के नेतृत्व में जारी रहेगी, जबकि व्यापारिक निर्यात में अपेक्षाकृत कमजोर वृद्धि देखी जा रही है।

इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार की अपेक्षा से अधिक मजबूत राजकोषीय स्थिति वृद्धि को और बढ़ावा दे सकती है। मुद्रास्फीति के संबंध में, ADO ने चालू वित्त वर्ष के लिए अपने पूर्वानुमान को 4.6 प्रतिशत पर बरकरार रखा है और उम्मीद है कि अगले वित्त वर्ष में यह मामूली रूप से घटकर 4.5 प्रतिशत हो जाएगी।

आयकर में बदलाव से लेकर विनिर्माण को बढ़ावा, बजट को लेकर रहेंगी ये उम्मीदें

23 जुलाई को मोदी सरकार का तीसरा बजट पेश होगा। नोमुरा के विश्लेषक सोनल वर्मा और ऑरोदीप नंदी का अनुमान है कि सरकार वित्त वर्ष 2025 के लिए अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को जीडीपी के 5.1% से घटाकर 5% कर देगी। यह एडजस्टमेंट कमजोर राजनीतिक जनादेश के बावजूद राजकोषीय स्थिरता बनाए रखने के लिए सरकार के दृढ़ संकल्प का संकेत देगा।

परिवहन विशेष न्यूज

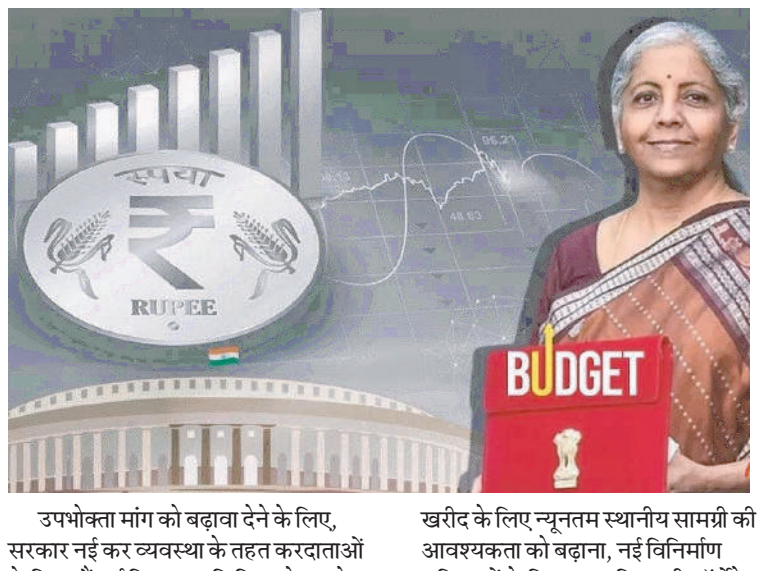

नई दिल्ली। 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। यह मोदी सरकार का तीसरा बजट होगा। इसी के साथ निर्मला सीतारमण के लिए यह लगातार पेश किए जाने के क्रम में उनका 7वीं बार का बजट होगा। अपकमिंग बजट सरकार के विजन और सुधार एजेंडे को लेकर खास होगा। ब्रोकरेज नोमुरा ने इस बजट को आकार देने के लिए पांच थीम को हाइलाइट किया है।

नोमुरा के विश्लेषक सोनल वर्मा और ऑरोदीप नंदी का अनुमान है कि सरकार वित्त वर्ष 2025 के लिए अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को जीडीपी के 5.1% से घटाकर 5% कर देगी। यह एडजस्टमेंट कमजोर राजनीतिक जनादेश के बावजूद राजकोषीय स्थिरता बनाए रखने के लिए सरकार के दृढ़ संकल्प का संकेत देगा।

आयकर में बदलाव की उम्मीद

उपभोक्ता मांग को बढ़ावा देने के लिए, सरकार नई कर व्यवस्था के तहत करदाताओं के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट को बढ़ाने पर विचार कर सकती है।

जो बिना छूट के कम दरें प्रदान करती है। बैंक ब्याज से प्राप्त आय के लिए छूट सीमा में भी वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा, 5 लाख रुपये से 15 लाख रुपये के बीच की आय वाले व्यक्तियों के लिए व्यक्तिगत आयकर दरों में कमी की संभावना है।

विनिर्माण को बढ़ावा देना

नोमुरा का अनुमान है कि सरकार घरेलू विनिर्माण को लेकर इस बजट में कुछ नए बदलाव पेश कर सकती है। इसमें सार्वजनिक सब्सिडी में इजाफा शामिल हो सकता है, जिसका अनुमान 23,000 करोड़ रुपये है। साथ ही ग्रामीण सड़कों और रोजगार पहलों के लिए फंडिंग बढ़ाई जा सकती है।

सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम का विस्तार कर सकती है और महिलाओं के लिए लखपति दीदी आर्थिक सशक्तिकरण पहल को फिर से शुरू कर सकती है।

बुनियादी ढांचे का विकास

सार्वजनिक पूंजीगत व्यय (capex) सरकार की आर्थिक रणनीति का एक बुनियादी पहलू बना रह सकता है। नोमुरा ने कुल पूंजीगत व्यय में वृद्धि का अनुमान लगाया है। नोमुरा के मुताबिक, यह अंतरिम बजट में 3.4% से बढ़कर जीडीपी का 3.5% हो जाएगा।

राज्य की मांगों के जवाब में, सरकार खरीद के लिए न्यूनतम स्थानीय सामग्री की आवश्यकता को बढ़ाना, नई विनिर्माण सुविधाओं के लिए 15% रियायती कॉर्पोरेट कर दर को बहाल करना शामिल हो सकता है।

इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक्स वैश्विक मूल्य श्रृंखला को एकीकृत करने पर 2019 की नीति में संसोधन किया जा सकता है। उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (Production-Linked Incentive) योजना को इलेक्ट्रॉनिक घटकों तक भी विस्तारित किए जाने की उम्मीद है।

सामाजिक क्षेत्र में व्यय बढ़ाना

बजट में विभिन्न योजनाओं के लिए आवंटन बढ़ाकर ग्रामीण क्षेत्र को प्राथमिकता दिए जाने की उम्मीद की जा रही है। इसमें आवास के लिए बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के लिए 50 साल की ब्याज मुक्त ऋण योजना के तहत बिना शर्त ट्रांसफर को भी बढ़ा सकती है।

मध्यम अवधि का आर्थिक दृष्टिकोण स्थापित करना

यह बजट हाल के चुनावों के बाद पहला महत्वपूर्ण वित्तीय रोडमैप है, जो सरकार के लिए अपने मध्यम अवधि के आर्थिक दृष्टिकोण को सामने रखने का एक महत्वपूर्ण अवसर है।

विश्लेषकों को उम्मीद है कि यह एक व्यापक योजना होगी जो 2047 तक एक विकसित अर्थव्यवस्था बनने की भारत की आकांक्षा को रेखांकित करेगी। इसमें अगले पांच वर्षों के लिए विशिष्ट उद्देश्यों का विवरण होगा।

इन शहरों में नहीं खुला है बैंक, चेक करें आरबीआई बैंक हॉलिडे लिस्ट

अगर आप किसी काम से बैंक जाने वाले हैं तो रुकें। आज कई शहरों में बैंक बंद है। दरअसल मुहर्रम के अवसर पर कई शहरों में बैंक हॉलिडे है। आपको बैंक जाने से पहले जरूर चेक कर लेना चाहिए कि कहीं आपके शहर में तो आज बैंक की छुट्टी नहीं है।

नई दिल्ली। आज देश के कई शहरों में बैंक बंद रहने वाला है। दरअसल, आज मुहर्रम के मौके पर बैंक हॉलिडे हैं। हालांकि, कई शहरों में बैंक आज भी खुले हैं। ऐसे में आपको आज बैंक जाने से पहले एक बार बैंक हॉलिडे लिस्ट जरूर चेक कर लेना चाहिए। आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा बैंक हॉलिडे लिस्ट जारी होती है। आप आरबीआई की वेबसाइट से भी बैंक हॉलिडे लिस्ट चेक कर सकते हैं।

आज इन शहरों में बंद हैं बैंक

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी बैंक हॉलिडे लिस्ट के अनुसार 17 जुलाई 2024 यानी आज मुहर्रम के साथ आशूरा, यू तिरोज सिंग त्योहार भी है। इस मौके पर आज पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, नई दिल्ली, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मेघालय, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, मिजोरम, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा के बैंकों में छुट्टी है। इसका मतलब है कि इन राज्यों के अलावा बाकी राज्यों के बैंक आज खुले हैं।

जुलाई में इतने दिन बंद रहेंगे बैंक

17 जुलाई के अलावा 3 दिन और बैंक की छुट्टी रहने वाली है।

21 जुलाई को रविवार की वजह से देशभर के बैंक बंद रहेंगे।

27 जुलाई को चौथा शनिवार है। इस वजह से इस दिन पूरे देश के बैंकों में छुट्टी हैं।

28 जुलाई को रविवार है। इस दिन भी देश के सभी बैंक बंद रहेंगे।

ये सर्विस रहेगी चालू

बैंक बंद होने के बावजूद बैंक की कई सर्विस चालू रहती है। बैंक हॉलिडे के दिन आप एटीएम की सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा नेट बैंकिंग और ऑनलाइन बैंकिंग का भी लाभ उठा सकते हैं। आपको बता दें कि नेट बैंकिंग और ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा चौबीस घंटे उपलब्ध रहती है। ग्राहक यूपीआई पेमेंट का भी इस्तेमाल कभी भी कर सकते हैं।

बेस्ट नो-कॉस्ट ईएमआई प्लान कैसे चुने? यहां जानें इस सवाल का जवाब

No-Cost EMI सुनने में जितना अच्छा लगता है उतना ही इसे सेलेक्ट करने में सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर नो-कॉस्ट ईएमआई प्लान सही से नहीं चुनते हैं तो आपको वित्तीय परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आज हम आपको बताएंगे कि आपको No-Cost EMI Plan सेलेक्ट करने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको बाद में कोई परेशानी न हो।

नई दिल्ली। कोई भी लोन हो या फिर किसी भी महंगे सामान की खरीद पर नो-कॉस्ट ईएमआई (No-Cost EMI) लोगों को काफी आकर्षित करता है। दरअसल, नो-कॉस्ट ईएमआई में कस्टमर को हर महीने किस्त देनी होती। इसमें कस्टमर को कोई अतिरिक्त ब्याज नहीं देना होता है। इसके अलावा नो-कॉस्ट ईएमआई में बिना कोई अतिरिक्त पैसे दिए ग्राहक आसानी से अपने बजट के हिसाब से सामान खरीद सकता है।

नो-कॉस्ट ईएमआई सुनने से पहले आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि आप सही नो-कॉस्ट ईएमआई प्लान चुन सकें।

No-Cost EMI ऑफर सेलेक्ट करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

ऑफर: आपको नो कॉस्ट ईएमआई प्लान सेलेक्ट करने के लिए आपको कई रिटेलर्स और लेंडर्स द्वारा दिए जाने वाले नो-कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन की तुलना करें। इन सभी द्वारा ऑफर किए जाने वाले प्लान को कंपेयर करने के बाद ही सेलेक्ट करें।

पात्रता: आपको रिटेलर या वित्तीय संस्थान द्वारा ऑफर किये जाने वाले नो-कॉस्ट ईएमआई की पात्रता मापदंड को भी ध्यान में रखें।

बजट: नो-कॉस्ट ईएमआई के लिए आपको

> आपको नो कॉस्ट ईएमआई प्लान सेलेक्ट करने के लिए आपको कई रिटेलर्स और लेंडर्स द्वारा दिए जाने वाले नो-कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन की तुलना करें। इन सभी द्वारा ऑफर किए जाने वाले प्लान को कंपेयर करने के बाद ही सेलेक्ट करें।

अपने बजट का ध्यान रखने की जरूरत है। इसके लिए आप पहले ईएमआई पीरियड और फिर सामान की टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करें और फिर अपना बजट के हिसाब से ही चीजें सेलेक्ट करें।

नियम व शर्तें: कोई भी प्लान को सेलेक्ट करने से पहले उसके नियम व शर्तों को ध्यान से पढ़ें। इसमें आप जरूर चेक करें कि कोई हिडन फीस या चार्ज तो नहीं लगा है।

समय पर भुगतान करें: आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप समय पर भुगतान करें ताकि आप लेट फीस व पेनल्टी से बच पाएं।

कैंसिलेशन विंडो: हमेशा कैंसिलेशन विंडो का ध्यान रखें ताकि आपको कोई कैंसिलेशन फीस का भुगतान न करना पड़ें।

प्रोसेसिंग चार्ज: अगर आप नो-कॉस्ट ईएमआई कैंसिल करते हैं तो आपको प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ सकती है। ऐसे में आपको प्रोसेसिंग फीस का भी ध्यान रखना चाहिए।

रिफंड प्रोसेस: अगर आप बीच में नो-कॉस्ट ईएमआई कैंसिल करते हैं तो आपको रिटेलर को सामान वापस करना पड़ेगा। ऐसे में रिफंड प्रोसेस को पूरा होने में कितना समय लगेगा इसका ध्यान रखें।

नो-कॉस्ट ईएमआई सेलेक्ट करने से पहले आपको अपनी वित्तीय स्थिति का ध्यान रखना होगा। इसके अलावा आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आप कहीं नो-कॉस्ट ईएमआई के चक्कर में फिजूलखर्ची न करें।

23 लाख बच्चों को फैसले का इंतजार, 40 से अधिक याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट कल करेगा सुनवाई

NEET-UG 2024 सुप्रीम कोर्ट गुरुवार यानी कल (18 जुलाई) नीट-यूजी 2024 में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए 40 से अधिक याचिकाएं सूचीबद्ध हैं। बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने 8 जुलाई को अपनी सुनवाई के दौरान NTA को यह खुलासा करने का आदेश दिया था कि प्रश्नपत्र लीक कब हुआ कैसे लीक हुआ आदि।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट विवादों से घिरी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी 2024 से जुड़ी याचिकाओं पर गुरुवार (18 जुलाई) को सुनवाई करेगा। यह परीक्षा 5 मई को आयोजित की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर 18 जुलाई की अपलोड की गई वाद सूची के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ 40 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इनमें राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की याचिका भी शामिल है।

शीर्ष अदालत ने 11 जुलाई को परीक्षा रद्द करने, दोबारा परीक्षा कराने और नीट-यूजी 2024 के आयोजन में कथित गड़बड़ी की जांच की मांग वाली याचिकाओं सहित अन्य याचिकाओं पर सुनवाई 18 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी थी।

केन्द्र ने किया था गड़बड़ी से इनकार

हलफनामे में केंद्र ने कहा कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास द्वारा किए गए डेटा विश्लेषण से पता चलता है कि न तो बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का कोई संकेत है और न ही उम्मीदवारों के एक स्थानीय समूह को लाभ होने का जिससे असामान्य अंक आए हैं।

23.33 लाख से अधिक छात्रों ने दी थी परीक्षा

बता दें कि 5 मई को 571 शहरों में 4,750 केंद्रों पर 23.33 लाख से अधिक छात्रों ने परीक्षा दी थी, जिसमें 14 विदेशी शहर भी शामिल थे। केंद्र और एनटीए ने शीर्ष अदालत में दायर अपने पहले के हलफनामों में कहा था कि परीक्षा को रद्द करना सही नहीं होगा और बड़े पैमाने पर गोपनीयता के उल्लंघन के किसी भी सबूत के अभाव में लाखों ईमानदार उम्मीदवारों को 'गंभीर रूप से खतरे में डाल देगा'।

ग्यारस को बड़े मंदिर में तुलसी के पौधे वितरित किए

चारभुजानाथ के छप्पन भोग 18 को

परिवहन विशेष अनूप कुमार शर्मा

भीलवाड़ा। श्री माहेश्वरी समाज श्री चारभुजा जी मंदिर ट्रस्ट के बड़े मंदिर में आज ग्यारस के दिन भक्तों को तुलसी के पौधे वितरित किए गए। ट्रस्ट मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि इस अवसर पर देवेंद्र सोमानी मुकेश सोमानी सत्यनारायण तोतला, सुनील जागेटिया शिवकुमार बिरला, गोपाल सोमानी उपस्थित थे चारभुजा नाथ को विशेष पोशाक पहनाई गई जिसमें विठ्ठल भगवान का श्रंगार कर चारभुजा को आकर्षक सजाया गया, ग्यारस के दिन शिकंजी प्रसाद एवं साबूदाना खिचड़ी का प्रसाद वितरित किया गया, बड़े मंदिर चारभुजा नाथ को 18 जुलाई को प्रातः 9 बजे से 12 तक छप्पन भोग दर्शन का आयोजन रहेगा 12 बजे महा आरती का आयोजन होगा

महावीर इंटरनेशनल मीरा व जायंट्स ग्रुप सहेली ने गो माता को लगाया छप्पन भोग

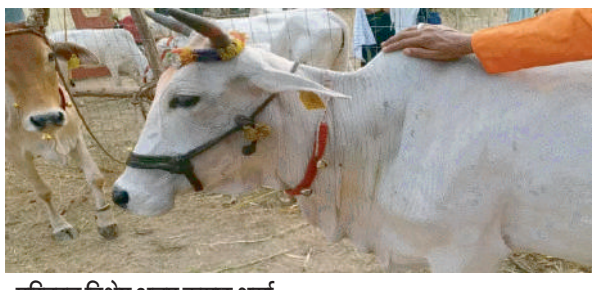

परिवहन विशेष अनूप कुमार शर्मा

भीलवाड़ा। मीरा व सहेली अध्यक्ष मंजु बापना ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंजु पोखरना की प्रेरणा से ज़ोन चेयरपर्सन मंजु खटोड़ की अध्यक्षता में वीरा पवन जिरावला के सहयोग से हरणी महादेव रोड स्थित काईन हाउस में गौमाता को छप्पन तरह के भोग जिसमे सभी तरह की हरि सब्ज़ियां, काकड़े, चारा, ड्राईफ्रूरट गुड आदि छप्पन तरह की वैराईटी खिलाई गई व गो माता की पूजा कर आरती की गई। महिलाओं ने गो माता के भजन ''छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मैरो मदनगोपाल'' मन मोह लिया। ज़ोन सचिव चंद्रा रांका ने जिरावला परिवार द्वारा हर महीने गो माता के लिये किये जाने वाले सेवा कार्य की सराहना की व धन्यवाद ज्ञापित किया।

कार्यक्रम में उपाध्यक्ष विमला रांका, उषा डोसी, रजनी जैन, संतोष जागेटिया, संध्या अग्रवाल, पूर्णिमा भक्ता, वंदना पोरवाल, भगवती आडवाणी, लीना पड़वानी, निर्मला सेन, नीलू मानसिंहका, वर्षा गर्ग, चेतना पराशर, शिवानी जैन, सुनीता, डिंपल काबरा, पुष्पा मेहता आदि उपस्थित थे।

दुनिया में छा गई भारत की यह एवरग्रीन चप्पल, इस देश में लाखों में बिक रही है नीली-सफेद रंग वाली स्लिपर

भारत में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां ये चप्पल किसी ने नहीं देखी होगी या इसका इस्तेमाल नहीं किया होगा।अगर में ऐसा कहूं की यह भारत के हर घर की पहचान है तो यह गलत नहीं होगा। जहां ये चप्पल भारत में आसानी से 60 रुपए से लेकर 100 रुपए तक के बीच में मिल जाती है वहीं यह सऊदी अरब में लाखों रुपए में बिक रही है।

नई दिल्ली। हमने बचपन से जिस चप्पल को अपने घरों में देखा अब उसकी कीमत जानकर आपको भी हैरानी हो सकती है। जी हां, मैं बात कर रही हूं हमारे घरों में और ज्यादातर बाथरूम स्लिपर के रूप में प्रयोग होने वाली चप्पल की कीमत अब लाखों रुपए हो गई है।

जिस चप्पल की मैं बात कर रही हूं उसमें क्लासिक भारतीय नीली और सफेद चप्पल है। यह चप्पल भारत में 60 रुपए से लेकर 100 रुपए तक आसानी से मिल सकती है लेकिन यही चप्पल सऊदी अरब में 4,590 रियाल (लगभग ₹ 100,000) में बेचा जा रहा है।

1 लाख रुपये की हवाई चप्पल?

भारत के लोगों ने जब भारत में मिलने वाले इस हवाई चप्पल को सऊदी अरब में देखा तो उनके होश उड़ गए। हैरानी तब और बढ़ गई जब उन्हें इस चप्पल का प्राइस पता चल। दरअसल, कुवैत के एक शॉप पर इस नीली-सफेद चप्पल को 4,500 रियाल (लगभग 1 लाख रुपये) में बेच रहा था।

इस चप्पल का एक वीडियो ट्विटर पर पोस्ट किया गया जिसमें आप इस चप्पल को डिस्प्ले में रखा हुआ देख सकते हैं। वीडियो के कैप्शन में लिखा था- ये है लेटेस्ट फैशन 'Zanouba' जिसकी कीमत 4500 रियाल (1 लाख रुपये) है।

का ऑपरेशन 'नन्हे फरिश्ते' लाया रंग, सात साल में 84000 से अधिक बच्चे किए गए रेस्क्यू

पीड़ित बच्चों को बचाने के लिए रेलवे पुलिस फोर्स RPF की ओर से शुरू किए गए ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के बेहद सुखद परिणाम मिले हैं। रेलवे ने बताया कि इस अभियान के तहत अब तक 84119 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है। 2018 में शुरू किए गए इस अभियान के माध्यम से विभिन्न चुनौतियों से जूझ रहे बच्चों को उनके घर तक पहुंचाने में मदद की गई है।

नई दिल्ली। आरपीएफ ने पिछले सात साल में रेल स्टेशन और ट्रेनों से 84,119 बच्चों को गलत हाथों में जाने से बचाया है। रेल मंत्रालय ने बताया कि आरपीएफ पिछले सात साल से नन्हे फरिश्ते नाम से चलाये जा रहे अभियान में अग्रणी रहा है। यह मिशन बच्चों के देखभाल और संरक्षण के लिए है।

मंत्रालय ने बताया कि 2018 में इस मिशन की शुरुआत हुई। इस वर्ष आरपीएफ ने कुल 17,112 पीड़ित बच्चों को बचाया, जिनमें घर से भागे, लापता, बिछड़े हुए, निराश्रित, अपहृत मानसिक रूप से कमजोर और बेघर बच्चे शामिल हैं। मंत्रालय ने वर्षवार आंकड़े देते हुए बताया कि वर्ष 2019 में कुल 15,932 बच्चों को बचाया गया। 2020 कोविड महामारी की चुनौतियों के बावजूद 5,011 बच्चों को बचाया गया। वहीं, 2021 में 11,907, 2022 में 17,756 और 2023 में 11,794 बच्चों को बचाया गया।

जिला कल्याण समिति का लिया जाता है सहयोग

मंत्रालय ने बताया कि 2024 के शुरुआती पांच महीनों में 4,607 बच्चों को बचाया है। मंत्रालय के अनुसार ट्रैक चाइल्ड पोर्टल पर बचाये गए बच्चों की जानकारी उपलब्ध है। मंत्रालय ने कहा, 'आरपीएफ बचाए गए बच्चों को जिला बाल कल्याण समिति को सौंप देती है। जिला बाल कल्याण समिति बच्चों को उनके माता-पिता तक पहुंचाती है।'

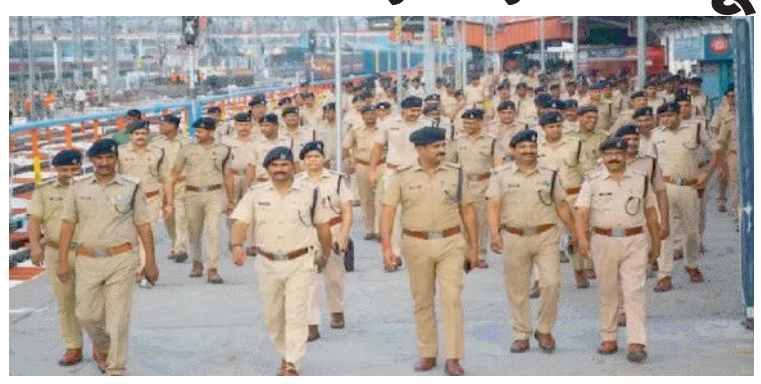

कांग्रेस ने विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरा

मनोरंजन सासमल, स्टेट हेड उडीशा

भुबनेस्वर: जब चारों दरवाजे खोले गए तो वह मंदिर को ठीक से नहीं देख सका। आइए रत्नों की शीघ्र गिनती करें। एएसओ पर हमले की घटना में दोषियों पर कार्रवाई क्यों नहीं? ऐसे कई मुद्दों पर कांग्रेस ने राज्य सरकार को घेरा है। पीसीसी अध्यक्ष शरत पटनायक ने मंदिर के चारों दरवाजे खोलने का मुद्दा उठाया और कहा, जब चारों दरवाजे खोले जाते हैं तो लोगों को परेशान किया जाता है। उन्होंने एडीपी की पढ़ाई के दौरान बलभद्र का चेहरा गिरने की घटना पर दुख व्यक्त किया और इसके लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। शरत ने मांग की कि किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश से घटना की जांच करायी जाये और रिपोर्ट मांगी जाये। दूसरे मामले में पिटाई के शिकार एएसओ को बदलने पर शरत ने कड़ा एतराज जताया। एक को पीटा जाएगा और उसे सज़ा मिलेगी? मुख्यमंत्री उड़िया अस्मिता की बात कर रहे हैं। अब बाहरी लोगों ने आकर ओडियनों को भगा दिया है। सरकार चुप क्यों है? शरत और पार्टी के अन्य प्रमुख नेताओं ने मांग की है कि त्वरित जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाये।

घटता शारीरिक श्रम, बढ़ती व्याधियां : विजय गर्ग

किसी देश में सेहत और बीमारी का संबंध सिर्फ इलाज की सहूलियतों और आबादी की तुलना में उपलब्ध अस्पतालों और डाक्टरों की संख्या से हो, जरूरी नहीं। लोगों को कई रोग इसलिए भी घेरते हैं, क्योंकि उनकी दिनचर्या सेहत से जुड़े कायदों के मुताबिक नहीं होती और लोग ऐसी दिनचर्या अपनाते हैं, जिससे उनके बीमार पड़ने की आशंका कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे कई अध्ययन और सर्वेक्षण हुए हैं, जो बताते हैं कि हमारे देश देश में साधन-संपन्नता बढ़ने के साथ लोग अपनी दिनचर्या और स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा लापरवाह हुए हैं। ऐसा ही एक अध्ययन हाल में 'द लैंसेट ग्लोबल हेल्थ' पत्रिका में प्रकाशित किया है। इसमें दावा किया गया है कि भारतीय शारीरिक सक्रियता के मामले में दूसरे कई देशों के नागरिकों से काफी पीछे हैं।

2019 में दुनिया के 197 देशों में सन 2000 से 2022 के मध्य कराए गए इस अध्ययन का उद्देश्य उद्देश्य विभिन्न देशों के वयस्क नागरिकों की दिनचर्या में शारीरिक सक्रियता की हिस्सेदारी और स्तर को नापना था। अध्ययन में 197 में से 163 देशों से मिले 507 सर्वेक्षणों का आकलन किया गया, जो दुनिया की कुल आबादी के 93 फीसद हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें से 167 सर्वेक्षण 2010 से पहले के, 268 सर्वेक्षण 2010 से 9 के मध्य के और 72 सर्वेक्षण 2020 और उसके बाद के हैं। रपट कहा गया है कि वैसे तो पूरी दुनिया में आम वयस्कों की शारीरिक सक्रियता में कमी आई है, लेकिन इसमें उच्च आय वाले एशिया प्रशां क्षेत्र के देशों के आंकड़े परेशान करने वाले हैं। भारत ऐसे देशों सूची में दूसरे स्थान पर है, जहां के वयस्कों में आलस्य यानी सुस्ती बढ़ने के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। रपट के मुताबिक आज से करीब पच्चीस वर्ष पहले भारत के वयस्कों का बाईस फीसद हिस्सा ऐसा था, जिसे शारीरिक सक्रियता के मामले में सुस्त माना जाता था। मगर 2010 में यह बढ़कर 34 और 2022 में लगभग 50 फीसद हो गया। कह सकते हैं कि कोविड महामारी के बाद वाले दौर में भारत के आधे वयस्कों की शारीरिक सक्रियता तकरीबन ठप हो चली है। 2030 तक इसके 60 फीसद तक पहुंचने का अनुमान है।

ताजा आंकड़े हमारे देश में 42 फीसद पुरुषों की शारीरिक निष्क्रियता दर्शाते हैं, तो स्त्रियों के मामले यह 57 फीसद बताया गया है। ऐसा संभवतः इसलिए है क्योंकि घरेलू कामकाज में स्त्रियों की भूमिका लगातार सिकुड़ रही है। यहां शारीरिक सक्रियता से आशय तेज चलने, दौड़-धूप वाले काम करने और ऊर्जा जलाने वाले व्यायाम है। हालांकि वैश्विक स्तर पर वयस्कों का निष्क्रियता संबंधी आंकड़ा वर्ष 2010 में 26.4 था, जो अब बढ़कर 31.3 फीसद हो गया है। कह सकते हैं कि इस निष्क्रियता में एक बड़ी भूमिका कोविड महामारी के दौर की हो सकती है। कोविड महामारी के दौरान सारे कामकाज इंटरनेट के जरिए घर बैठे कराने का चलन स्थापित हुआ, जो बाद परिपाटी में बदल गया। इससे लोगों का घर से बाहर निकलना कम हो गया। यहां तक कि 'वर्क फ्राम होम' यानी 'घर से काम की संस्कृति और विकसित हो जाने से दफ्तर जाने की अनिवार्यता में भी भारी कटौती हो गई है। इससे भी वयस्कों की शारीरिक निष्क्रियता बढ़ी है।

शारीरिक सक्रियता में कमी को लेकर इसलिए चिंता जताई जा रही है कि व्यायाम, दौड़-धूप वाला कोई काम न करने, पैदल न चलने का असर यह होता है कि शरीर पर चर्बी बढ़ने लगती है और कई अंग भारी वसा और निष्क्रिय जीवनशैली के असर से पैदा बोझ के तले दबते चले जाते हैं। इन दशाओं में मनुष्य का पाचनतंत्र कमजोर या बीमार हो जाता है। भोजन से मिली ऊर्जा खर्च न हो पाने की दशा में शरीर पर बसा और अतिरिक्त मांस के रूप में जमा हो जाती है। इससे मोटापा, उच्च रक्तचाप, हृदयरोग और पाचन तंत्र की कई समस्याएं बढ़ जाती हैं। इन बीमारियों को जीवनशैली संबंधी बीमारियों के रूप में पहचाना जाता है, जो दुनिया के लिए एक बड़े स्वास्थ्य संकट की तरह सामने आ रही हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2017 में अपने एक वृहद अध्ययन में बताया था कि भारत में 61 फीसद गैर-संक्रामक मौतों के पीछे लोगों की निष्क्रिय दिनचर्या है दुनिया के 19 लाख लोगों की दैनिक शारीरिक सक्रियता का अध्ययन करके पेश की गई इस रपट में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अंदाजा लगाया था कि इस वक्त दुनिया में करीब 140 करोड़ लोगों की शारीरिक सक्रियता काफी कम है, लेकिन उस वक्त इस रपट में बताया गया था कि भारत के 24.7 फीसद पुरुषों और 43.3 फीसद महिलाओं को अपने हाथ-पांव हिलाने में ज्यादा यकीन नहीं है। यह आंकड़ा अब बढ़ चुका है। मगर पड़ोसी देश चीन ने 'हेल्दी चाइना 2030' अभियान चलाया है। इसी तरह आस्ट्रेलिया ने 2030 तक अपने 15 फीसद नागरिकों को व्यायाम में सक्रिय बनाने का लक्ष्य रखा है। ब्रिटेन में 2030 तक पांच लाख नए लोगों को व्यायाम से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि अमेरिका में एक हजार शहरों को 'फ्री फिटनेस' से जोड़ने का अभियान चलाया गया है।

महत्त्वपूर्ण बात यह है कि यह सुस्ती हमारी पूरी जीवनशैली और कार्य संस्कृति में समाई ई हुई है। और इसलिए यह एक चेतावनी है। इसलिए ऐसे अध्ययनों की गंभीरता को समझते हुए भारतीयों को अपनी दिनचर्या में बदलाव को लेकर तुरंत सतर्क हो जाने की जरूरत है। इस चेतावनी का सबसे अहम पहलू शारीरिक परिश्रम से जुड़ा है, जिसकी भारतीय जीवन में जबर्दस्त अनदेखी हो रही है। इसमें महिलाओं और नहीं, बच्चों की बदलती जीवनशैली के भी संकेत निहित हैं।

कारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और अब लोग छोटे- मोटे कामों में भी कारों का इस्तेमाल करने लगे हैं। यही नहीं, ई-कामर्स की बदौलत अब तो बाजार खुद लोगों के घरों में आ पहुंचा है। ऐसे में अधिक से अधिक कसरत आंखों और हाथ की उंगलियों की ही होती। है अन्यथा लोग हाथ-पांव हिलाए बिना टीवी के सामने जमे रहते हैं। । कहीं कोई चलने-फिरने का दबाव नहीं, जरूरत नहीं। यह सही है कि चिकित्सा विज्ञान की बदौलत इंसान की औसत में इजाफा हो है, लेकिन लोग ऐसी बीमारियों से ग्रस्त रहने लगे हैं, जिन्हें जीवन-शैली सग्रस्त की बीमारियां कहा जाता। है। 'लैंसेट' ' में 2017 में प्रकाशित अध्ययन 'ग्लोबल बर्डन आफ डिजीज' ' में कहा गया था कि अमीर देशों के लोग यह समझने लगे हैं कि सेहत कितनी जरूरी है, इसलिए वे शारीरिक श्रम को महत्त्व देने लगे हैं, लेकिन भारत जैसे देशों में यह बात समझी नहीं जा रही। लिहाजा, गरीब और विकासशील देशों में अमीर मुल्कों की तुलना में लोग ज्यादा दिन बीमार रहते हैं।

सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य शैक्षिक स्तंभकार मलोट

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com

(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। **RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023**